A Daily News Magazine

भोपाल

शुक्रवार, 08 मई, 2026

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 245, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

मुस्लिमों ने ओवैसी-अजमल को छोड़ कांग्रेस को वोट क्यों दिया?

मुकेश कुमार

असम और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुसलमानों ने मतदान किया है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव है, एक बड़ा मोड़ है। इससे लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राजनीति को बड़ी ऊर्जा मिलेगी। ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है इसे समझने के लिए हमें सांप्रदायिक राजनीति के दो ध्रुवों की प्रतिक्रियाओं को देखना होगा। असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आने के बाद से बीजेपी और उसके समर्थक कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी बताने का अभियान चला रहे हैं। वे साबित करने पर आमादा हैं कि कांग्रेस अब केवल मुसलमानों की पार्टी रह गई है। मज़ेदार ये है कि असदुद्दीन ओवैसी और बदरूद्दीन अजमल जैसे नेता भी कांग्रेस से परेशान हैं। वे भी कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं और मुसलमानों से कह रहे हैं वे उनकी छतरी तले आ जाएं, कांग्रेस पर भरोसा न करें।

यानी सांप्रदायिक राजनीति के दोनों ध्रुव कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। एक उसे मुस्लिमपरस्त पार्टी घोषित कर रहा है तो दूसरा मुसलमानों को कांग्रेस से डरा रहा है। और इसकी वज़ह ये है कि कांग्रेस ने असम और बंगाल में जो 21 सीटें जीतीं हैं उनमें से 19 पर मुस्लिम उम्मीदवार विजयी हुए।

इस आँकड़े को देखने के बाद पहली नज़र में किसी को भी लग सकता है कि अगर बीजेपी कांग्रेस पर मुस्लिम लीग 2.0 होने का आरोप लगा रही है तो क्या वह सही नहीं है? लेकिन अगर आप इन आँकड़ों के पीछे झाँकेंगे तो एक दूसरी ही सचाई नज़र आएगी। कांग्रेस ने इन दोनों राज्यों में कुल 390 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 21 सीटें जीतीं, जिनमें से 19 असम की हैं और दो बंगाल की।

बंगाल में उसने 292 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे जिसमें से मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या 63 थी यानी 229 उम्मीदवार गैर मुसलमान थे। राज्य में 27-30 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है और उसके मद्देनज़र ये पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं थी। इसके बावजूद दो मुसलमान जीत गए जबकि एक भी हिंदू उम्मीदवार नहीं जीता। क्योंकि राज्य में दो तरह का ध्रुवीकरण हुआ। एक तो बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक और दूसरा सांप्रदायिक। ऐसी सूरत में कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम बहुल इलाक़ों से ही जीत पाए।

ठीक ऐसा ही असम में हुआ। असम में कांग्रेस ने 99 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से केवल 20 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे यानी 79 उम्मीदवार ग़ैर मुस्लिम थे। असम में मुसलमानों की आबादी 34 फ़ीसदी के आसपास है। यानी उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में बहुत कम सीटें दी गईं। फिर भी 20 में से 18 उम्मीदवार जीत गए।

बंगाल की तरह ही असम में भी कांग्रेस की सभी 19 सीटें ऐसे ही इलाक़ों से आई हैं। उसका एकमात्र हिंदू उम्मीदवार जयप्रकाश दास भी ऐसी सीट से विजयी हुआ है, जहाँ मुसलमानों की आबादी अच्छी-खासी है।

चुनाव आयोग ने परिसीमन के ज़रिए मुस्लिम बहुल सीटों पर बड़ा खेल कर दिया था। असम में पहले मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 35 थी जिस घटाकर 22 कर दिया गया। यानी बीजेपी ने 13 सीटें धोखाधड़ी से जीतीं। बंगाल में कांग्रेस को दोनों सीटें मुर्शिदाबाद से मिली हैं। मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल इलाक़ा है। मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और बदरुद्दीन अजमल की AIUDF जैसी पहचान-आधारित पार्टियों को नकारते हुए कांग्रेस जैसे सेकुलर और समावेशी मंच की ओर रुख किया है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए स्वस्थ और आशाजनक घटना है।

कांग्रेस ने बहुसंख्यक हिंदू और अन्य समुदायों के उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन ध्रुवीकरण के माहौल में हिंदू वोट बीजेपी की ओर मजबूती से शिफ्ट हो गए, जबकि मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास केंद्रित हुए। बदरुद्दीन अजमल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने ढ्ढष्ठस्न को खत्म करने की कोशिश में 'कुआं खोदा और खुद गिर गई', लेकिन असल में यह मुस्लिम वोटरों का रणनीतिक फैसला था। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय, पहचान-केंद्रित पार्टी को ठुकराकर एक राष्ट्रीय, समावेशी विकल्प चुना।

बीजेपी समर्थक मीडिया केरल का उदाहरण भी दे रहा है। वह कह रहा है कि यूडीएफ गठबंधन की घटक भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के 22 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। ये सही है, लेकिन मुस्लिम लीग़ की तो पहचान ही मुस्लिम पार्टी की है। कांग्रेस के अपने 63 विधायकों में केवल 8 मुस्लिम हैं; बाकी हिंदू और ईसाई हैं। कुल मिलाकर मुस्लिम वोटरों ने IUML के साथ मिलकर कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन यह गठबंधन की मजबूरी थी, न कि कांग्रेस का मुस्लिमीकरण।

पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 99 सांसदों में सिर्फ 9 मुस्लिम हैं यानी करीब 10 प्रतिशत, जबकि मुसलमानों की आबादी 14.5 फ़ीसदी है। यानी आबादी से भी कम प्रतिनिधित्व। देश भर में कांग्रेस के कुल 664 विधायक हैं। इनमें से में लगभग 78 प्रतिशत हिंदू हैं। बाक़ी के 22 फ़ीसदी में ग़ैर हिंदू यानी जैन, सिख, ईसाई और मुसलमान हैं। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस के नब्बे फ़ीसदी विधायक हिंदू हैं। कांग्रेस अभी भी 'सभी की पार्टी' है, न कि किसी एक समुदाय की।

मुस्लिम समुदाय का यह शिफ्ट कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पिछले दो दशकों में ओवैसी और अजमल की पार्टियां मुस्लिमों को सुरक्षा देने का दावा करती रहीं। उन्होंने पहचान की राजनीति पर जोर दिया- कभी ट्रिपल तलाक, कभी CAA-NRC, कभी स्थानीय मुद्दों को मुस्लिम को आकर्षित करने से उठाया।

हालाँकि ये कहना जल्दबाज़ी होगी कि मुस्लिम मतदाता अब संकीर्ण कम्युनल प्लेटफॉर्म से आगे निकल चुके हैं और वे विकास, रोजगार, शिक्षा और समावेशी शासन चाहते हैं, जो कांग्रेस जैसे बड़े सेकुलर दलों से बेहतर जुड़ता है। लेकिन उनकी यह 'स्ट्रैटेजिक वोटिंग' उदाहरण है कि बीजेपी के हिंदू कंसोलिडेशन के खिलाफ मुस्लिम वोटर अब एक बड़े सेकुलर छत्र के नीचे आ रहे हैं।

भारतीय लोकतंत्र के लिए यह बेहद अच्छी खबर है। अगर मुस्लिम समुदाय ओवैसी-जैसे नेताओं को ठुकराकर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को अपना समर्थन दे रहा है, तो यह साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को कम करने की दिशा में कदम है। इस शिफ्ट का एक और सकारात्मक पहलू ये भी है कि मुस्लिम युवा वोटरों का सोच बदल रहा है। आज का मुस्लिम युवा सोशल मीडिया, शिक्षा और आर्थिक आकांक्षाओं से प्रभावित है। वह जानता है कि AIMIM या AIUDF जैसी छोटी पार्टियां संसद या विधानसभाओं में मुट्ठी भर सीटें जीत सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय नीति-निर्माण में असर नहीं डाल सकतीं। कांग्रेस जैसे दल के साथ जुड़कर वे बड़े मुद्दों–आरक्षण, रोजगार, किसान कल्याण–पर अपनी आवाज मजबूत कर सकते हैं। यह कोई 'मुस्लिमीकरण' नहीं, बल्कि लोकतंत्र की परिपक्वता है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

'ऑपरेशन सिंदूर' अभियान अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी

● एक साल पूरे होने पर सेना बोली, आतंकवाद से लड़ते रहेंगे

भारती ने कहा-सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा हमला दोबारा न हो

जयपुर (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। सेना ने यह भी कहा कि यह अभियान अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। गुरुवार को भारतीय वायुसेना, नौसेना और थलसेना के सैन्य अभियानों के प्रमुख जयपुर के साउथ वेस्टर्न कमांड में जुटे।

यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सैन्य अभियान के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। इस अभियान को पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ पिछले कई दशकों में भारत का सबसे व्यापक सैन्य अभियान बताया गया।

हमारी कार्रवाई में नरमी की गुंजाइश नहीं होती

एयर मार्शल अवधेश कुमार बोले– हम हमेशा जिओ और जीने दो के सिद्धांत के साथ जीते हैं। जब हमारी शांति की इच्छा को कमजोरी समझ लिया जाए और हमारी चुप्पी को हमारी अनुपस्थिति मान लिया जाए, तो कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जब हम कार्रवाई करते हैं, तो उसमें किसी तरह की नरमी की गुंजाइश नहीं होती। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। सेनाओं को पूरी ऑपरेशन फ्रीडम दी गई थी।

सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं

डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राजीव घई ने कहा– ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि 'आत्मनिर्भर' केवल एक नारा नहीं है, बल्कि वास्तव में हमारी शक्ति को कई गुना बढ़ाने वाला है। आज हमारे 65 फीसदी से अधिक रक्षा उपकरण देश में ही बनाए जा रहे हैं। सेना उन्हीं हथियारों का उपयोग कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह संदेश दिया कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी ठिकाना अब सुरक्षित नहीं है। घई ने दुष्यंत कुमार के शेर सुनाए। कहा– सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा।

थम नहीं रहा बवाल बंगाल में भारी उबाल

● शुभेन्दु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद बम ब्लास्ट

पानीहाटी में पांच बीजेपी कार्यकर्ता घायल,जांच हुई तेज

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हिंसा जारी है। कोलकाता के नजदीक आने वाले मध्यमग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीएम की हत्या के बाद बम अटैक की घटना भी सामने आई है। इसमें पांच बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। बम हमले की यह घटना पीएम चंद्रनाथ रथ की हत्या के कुछ घंटे बाद हुई। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के

पानीहाटी इलाके में देर रात हुए बम हमले में बीजेपी के पांच समर्थक घायल हो गए।

● **अधीर रंजन चौधरी ने कड़ी कार्रवाई की मांग की–** कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ राथ की हत्या पर कहा कि बंगाल में कानून की हालत देखिए, यहां गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है। दरिंदों के पनपने के लिए यह सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, चुनाव के नतीजों के बाद जब लोग शांति की उम्मीद कर रहे थे तब भी हम खून–खराबा होते देख रहे हैं।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा-ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित है नवीन भवन

भोपाल नगर निगम का नवीन भवन बनेगा सुशासन का प्रतीक : सीएम

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपालवासियों को भोपाल नगर निगम के नवीन मुख्यालय भवन की बधाई देते हुए कहा कि देश की क्लीन और ग्रीन कैपिटल, झीलों की नगरी भोपाल के नगर निगम का यह भवन सुशासन का प्रतीक बनेगा। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई ने जन सेवा को शासन का आधार माना था। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. वाजपेयी के नाम पर स्थापित अटल भवन सुलभ, सुव्यवस्थित और पारदर्शी सेवाओं का केंद्र होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल नगर पालिक निगम के नवनिर्मित मुख्यालय 'अटल भवन' के लोकार्पण अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि यह आधुनिक भवन शहर में सुशासन, बेहतर नागरिक सुविधाओं और विकास के नए संकल्प का प्रतीक बनेगा।

● **कहा–भवन से नागरिकों को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर होंगी उपलब्ध**

संदेश–भोपाल रहेगा स्वच्छता में नंबर-वन– मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगर पालिक निगम भोपाल के नवनिर्मित भवन में फीता खोलकर भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने भवन की शिलापट्टिका का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवनिर्मित भवन का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वच्छता शपथ पटल पर लिखा कि 'भोपाल स्वच्छता में रहेगा नंबर-वन'। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल नगर पालिक निगम द्वारा नीमच जिले के देवरी में लगभग 14 करोड़ रूपए की लागत से पीपीपी मोड पर विकसित की गई सौर ऊर्जा परियोजना का भी रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अंगवस्त्रम् तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया।

भोपाल को मेट्रोपॉलिटिन सिटी के रूप में किया जा रहा है विकसित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल नगर पालिक निगम का यह भवन ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इस भवन का आकल्पन नागरिकों को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। भवन में सूर्य के प्रकाश और वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था है, जो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित भारतीय वास्तुकला के सिद्धांतों के अनुरूप है। यह भवन अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा नीमच के ग्राम देवरी में स्थापित 10.5 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण भी किया है। इस भवन की बिजली आपूर्ति ओपन एक्सेस से नीमच के संयंत्र से की जाएगी। परिसर की पार्किंग में भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह भवन ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत उदाहरण है। प्रदेश की राजधानी भोपाल का गौरव दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। भोपाल को मेट्रोपॉलिटिन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ को भोपाल से जोड़ते हुए यह क्षेत्र विकास के नए सोपान तय करेगा।

शरद की सुबह

कोई नियम नहीं
सुन कर वह हँसा

कोई कानून नहीं
सुन कर वह हँसा

कोई न्याय नहीं
सुन कर वह हँसा

कोई नैतिकता नहीं
सुन कर वह हँसा

कोई मानवता नहीं
सुन कर वह हँसा

कोई शर्म नहीं
सुन कर वह हँसा

बहुत अत्याचार है
सुन कर वह हँसा

ये पाप है
सुन कर वह हँसा

ये धर्म नहीं
सुन कर वह हँसा

उसकी हँसी से जाना
तानाशाह कैसे हँसता है।

– चंद्रशेखर साकल्ले

हर धार्मिक प्रथा को कोर्ट में चुनौती देना ठीक नहीं

● सबरीमाला केस में आ गई सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ● कहा-इससे सैकड़ों केस आएंगे,धर्म-समाज पर असर पड़ेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर लोग धार्मिक प्रथाओं और धर्म के मामलों को संवैधानिक अदालत में चुनौती देने लगेंगे, तो इससे धर्म और सभ्यता पर असर पड़ सकता है।

कोर्ट ने कहा कि इससे सैकड़ों याचिकाएं आएंगी और हर रिवाज पर सवाल उठने लगेंगे। यह टिप्पणी नौ जजों की संविधान पीठ ने की, जो अलग-अलग धर्मों में धार्मिक आजादी के दायरे और महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। इसमें केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ा मामला और दाऊदी बोहरा समुदाय का केस भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 40 साल पुरानी जनहित याचिका की वैधता पर सवाल उठाए थे। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर हर व्यक्ति धार्मिक प्रथाओं पर सवाल उठाएगा, तो भारतीय समाज पर असर पड़ेगा, क्योंकि यहां धर्म समाज से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने कहा, हर अधिकार पर सवाल उठेंगे-मंदिर खुलने या बंद होने तक के मामले कोर्ट में आएंगे। जस्टिस एम एम सुन्द्रेश ने कहा कि अगर ऐसे विवादों को लगातार अनुमति दी गई, तो हर व्यक्ति हर चीज पर सवाल उठाएगा। उन्होंने कहा कि इससे धर्म टूट सकते हैं और संवैधानिक अदालतों पर भी असर पड़ेगा।

मामला दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ा है

यह मामला दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ा है। समुदाय के केंद्रीय बोर्ड ने 1986 में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें 1962 के फैसले को चुनौती दी गई थी। उस फैसले में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन एक्ट, 1949 रद्द कर दिया गया था। इस कानून के तहत किसी सदस्य को समुदाय से बाहर करना गैरकानूनी था। 1962 के फैसले में कहा गया था कि धार्मिक आधार पर यह ठीक नहीं है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 08 मई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

विजय थलपति की शपथ ग्रहण पर सस्पेंस खत्म!

● बहुमत साबित करने के बाद ही सीएम बन सकते हैं टीवीके चीफ

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में कौन बनेगा मुख्यमंत्री यह सस्पेंस अब खत्म हो गया है। गुरुवार सुबह विजय एक बार फिर राज्यपाल से मिले। लेकिन अब खबर आई है कि विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की शपथ तभी ले सकते हैं जब उनके पास बहुमत का आंकड़ा हो। सियासी गलियारों में हलचल तेज है। और अब समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि विजय राज्य में तभी शपथ ले पाएंगे जब उनके पास बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त विधायक हों। तमिलनाडु के राज्यपाल प्रदेश में एक स्थाई सरकार चाहते हैं। उनका मानना है कि जैसे ही बहुमत साबित होगा, विजय शपथ ले सकते हैं। लोक भवन के बाहर टीवीके प्रमुख विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाने और उनके तुरंत शपथ ग्रहण की मांग करते हुए टीवीके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। उनके के दो समर्थक लोक भवन के बाहर पोस्टर पकड़े हुए दिखाए दिए। लेकिन राज्यपाल ने कहा कि बिना बहुमत के वह उन्हें नहीं बुला सकते हैं।

विजय को सरकार बनाने दें: स्टालिन

डीएमके प्रमुख स्टालिन ने कहा कि सी जोसेफ विजय की सरकार बनाने दें। डीएमके अगले छह महीने तक बिना किसी हस्तक्षेप के नई सरकार को देखेगी और उसके बाद कोई फैसला लेगी। स्टालिन ने संकेत दिया कि फिलहाल डीएमके राज्य में ना तो संवैधानिक संकट चाहती है और ना ही जल्द दोबारा चुनाव। उन्होंने कहा कि नई सरकार को योजनाओं को जारी रखना चाहिए।

भोपाल में डॉक्टर सप्लाई कर रहा था नकली नोट

● पश्चिम बंगाल से लाया था, पाकिस्तानी कागज पर छपे हैं

● यूनाइटेड किंगडम सीरीज का फोन नंबर करता था इस्तेमाल

भोपाल। भोपाल की कोहेफिजा पुलिस ने पश्चिम बंगाल के एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 500 रुपए के 280 नकली नोट बरामद किए हैं। इनकी कुल कीमत 1.40 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी खुद को एमबीबीएस डॉक्टर बता रहा है, जो नोट मिले हैं। पुलिस को उसके पास से एक आईफोन, एक पेन ड्राइव और विदेशी सीरीज (+44) का मोबाइल नंबर भी मिला है। शुरुआती जांच में पुलिस को संदेह है कि आरोपी किसी

विशेष विचारधारा से प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से उसे कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। पूरी कार्रवाई को पुलिस ने बुधवार की दोपहर को अंजाम दिया, जबकि गुरुवार को इसका खुलासा किया है।

सैफिया कॉलेज ग्राउंड के पास पकड़ा गया- कोहेफिजा थाना प्रभारी केजी शुक्ला ने बताया कि बुधवार दोपहर सूचना मिली थी कि सैफिया कॉलेज ग्राउंड के पास एक युवक कम कीमत में नकली नोट खपाने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सैफुल इस्लाम पिता अनवर-उल इस्लाम (27) बताया। उसका कहना था कि वह ये नोट पश्चिम बंगाल से अपने एक दोस्त से लेकर आया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह वर्ष 2024 से इस धंधे में सक्रिय है। पहले भी दो बार भोपाल आकर नकली नोट खपा चुका है। मई 2025 से वह भोपाल की गुलमोहर कॉलोनी में किराए से रह रहा था। इसी दौरान उसने शादी भी कर ली।

दस दिन में 60 हजार के नकली नोट खपाए- उसने बताया कि वह दो लाख रुपए की नकली करेंसी 60 हजार रुपए में खरीदकर लाया था। 10 दिनों में वह करीब 60 हजार रुपए के नकली नोट बाजार में चला चुका है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी भोपाल में 300 रुपए असली लेकर बदले में 500 रुपए का नकली नोट देता था। आरोपी ने बताया कि वह बिना मेहनत के जल्दी अमीर बनने की चाह में इस कारोबार में उतरा।

पाकिस्तान और नेपाल के कागज पर छपे नोट- पुलिस के मुताबिक जब्त नोट नेपाल और पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले कागज जैसे पेपर पर छपे हैं। ऐसे में जांच अब अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय एंगल से भी की जा रही है। आरोपी की पहचान सैफुल इस्लाम (27) निवासी पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से विदेशी नंबरों पर बातचीत के संकेत मिले हैं।

● 10000 किमी की मारक क्षमता, पूरी दुनिया की नींद उड़ी

महाविनाशक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा भारत

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत अपनी स्वदेशी रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि के लेटेस्ट और सबसे घातक वर्जन के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। संस्कृत में अग्नि का अर्थ आग होता है और यह मिसाइल अपने नाम के अनुरूप ही रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाली है। यह मिसाइल एक साथ कई परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है, जो भारत की रणनीतिक ताकत को पूरी तरह से बदलकर रख देगी। वर्तमान में दुनिया के केवल पांच देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है। ये देश हैं-अमेरिका, रूस,चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अब इस सूची में भारत भी अपनी अग्नि-6 के साथ अपनी स्थिति बेहद मजबूत करने जा रहा है। अग्नि 6 भारत की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, जिसे खास तौर पर भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इस मिसाइल की संभावित मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। इतनी लंबी दूरी की रेंज के साथ, भारत की रणनीतिक पहुंच अब केवल क्षेत्रीय नहीं रह जाएगी, बल्कि यह वैश्विक स्तर की हो जाएगी।

दिग्गजों के बराबर भारत, एक नए युग की शुरुआत

यह एडवांस तकनीक अब तक मुख्य रूप से अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास ही मौजूद थी लेकिन अग्नि-6 के साथ, भारत अब तकनीकी रूप से ठीक उसी स्तर पर खड़ा हो रहा है। अग्नि-6 का यह विकास केवल एक रक्षा उपकरण का निर्माण नहीं है, बल्कि यह भारत को एक नए दौर में ले जा रहा है। गाइडेड मिसाइल तकनीक और 10,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता यह साबित करती है कि भारत अब केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि ग्लोबल पावर के पैमाने पर एक नया मानदंड स्थापित कर रहा है।

सम्राट कैबिनेट में नीतिश के बेटे समेत अब 32 मंत्री

● पीएम ने पूर्व सीएम को बुलाया, हाथ पकड़कर पास लाए

पूर्व मुख्यमंत्री नीतिश ने प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखा

पटना (एजेंसी)। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के 22 दिन बाद गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार किया गया। मेगा इवेंट में नीतिश के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए। नई कैबिनेट में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी (आर)-2, हम और लोसपा से एक-एक मंत्री हैं। 25 मिनट चले इस कार्यक्रम में एक साथ 5-5 विधायकों ने शपथ ली है। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने नीतिश कुमार को अपने पास बुलाया।

बीजेपी ने 3 चेहरों को ड्रॉप किया

सम्राट कैबिनेट में बीजेपी कोटे से 15 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें 5 नए चेहरे हैं, वहीं तीन पुराने लोगों को इस बार मौका नहीं मिला। इनमें बीजेपी के सीनियर लीडर मंगल पांडेय, बेगूसराय के बछवाड़ा से विधायक सुरेंद्र मेहता और प. चंपारण से नारायण प्रसाद का नाम शामिल है।

पहली बार 50 हजार जवानों की अलग ड्रोन फोर्स

● बीएसएफ और आईटीबीपी में भी बनेंगी, तैयारी शुरू ● किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले यही प्रहार करेंगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर, रूस-यूक्रेन और अमेरिका-इजराइल-ईरान जंग के बाद भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान ने एक 'ड्रोन फोर्स' बनाने का फैसला किया है। यह फोर्स किसी भी सैन्य कार्रवाई में 'फर्स्ट रेस्पोंडर' (पहली जवाबी कार्रवाई) के तौर पर तैनात की जाएगी। इसे डेटा और कॉग्निटिव वारफेयर फोर्स का तकनीकी का सपोर्ट होगा। इंटीग्रेटेड रक्षा मुख्यालय के अनुसार इस फोर्स के लिए अभी 50 हजार सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगले 3 साल में 15 नए 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' बनाए जाएंगे। यहां सिम्युलेटर और वर्चुअल रियलिटी के जरिए रीयल-टाइम बैटल ट्रेनिंग दी जाएगी। भविष्य में बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे सुरक्षा बलों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

AI जनरेटेड

डिफेंस ईकोसिस्टम भी नया तीनों सेनाएं एक

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने खुद को रक्षा उत्पादन में काफी मजबूत किया है। यह 1.54 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तीनों सेनाओं की थिएटर कमान बन रही है। दुश्मन के सस्ते ड्रोन्स से निपटने के लिए अब किफायती 'सॉफ्ट किल' (जैमिंग/स्पूफिंग) और 'हार्ड किल' (लेजर-आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन) तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन फोर्स का विचार पिछले साल तब आया, जब पाकिस्तान ने 1,000 ड्रोन्स से हमला किया। उसका मकसद हमारे एयर डिफेंस गैप्स को समझना और महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सस्ते ड्रोन्स के जरिए आर्थिक नुकसान पहुंचाना था।

मिसाइलों का मेंटेनेंस भारत में ही होगा

इधर यूरोपीय रक्षा दिग्गज कंपनी एमबीडीए के साथ भारतीय वायुसेना का एक अहम समझौता हुआ है। समझौते के तहत राफेल लड़ाकू विमान में लगने वाली मीका एयर टू एयर मिसाइलों का रखरखाव अब भारत में ही वायुसेना करेगी। इसके लिए देश में इनके 'मेंटेनेंस, रिपेयर, मिड लाइफ ओवरहॉल' की सुविधा तैयार की जाएगी। यह कदम भारत द्वारा प्रस्तावित 114 अतिरिक्त मल्टीरोल लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण से ठीक पहले उठाया गया है। बता दें कि यह 60-80 किमी रेंज की छोटी से मध्यम दूरी वाली मिसाइल है।

धोखेबाज दलों को जनता दफन करेगी

योगी बोले-देशद्रोहियों ने सिर उठाया तो काम तमाम

सहारनपुर (एजेंसी)। 'सहारनपुर पहले फतवों, दंगों और पलायन के लिए जाना जाता था। हर बात पर फतवे जारी होते थे। खाना कैसे खाना है, इस पर भी फतवा जारी होता था। हमने यहां फतवों की संस्कृति नहीं, बल्कि एटीएस सेंटर दिया है। अब यहां हमारे कमांडो निगरानी करते हैं। कोई भी देशद्रोही सिर उठाएगा तो उसका काम तमाम तय है।' सीएम योगी ने गुरुवार को सहारनपुर को 2131 करोड़ की 325 विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए यह बात कही। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत पर योगी ने कहा- बंगाल में पहली बार भाजपा ने सरकार बनाकर सभी राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाया है। जो समाज के विभाजन के लिए व्यूह रचना कर रहे थे, उन्हें आईना दिखाया है। इस जीत ने बता दिया कि जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच सक्रिय रहें, तो सरकार दोहराई जाएगी। वरना जनता देश को धोखा देने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में देर नहीं लगाएगी। इससे पहले, योगी ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र बांटे।

पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ निपटाएंगे सास-बहू का झगड़ा

● एससी ने कपूर फैमिली विवाद में नियुक्त किया मध्यस्थ

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एक हाई प्रोफाइल बिजनेस फैमिली के झगड़े के सुलझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कपूर फैमिली विवाद में मध्यस्थ के तौर पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति कपूर फैमिली के पारिवारिक ट्रस्ट से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए की गई है। यह विवाद इस कानूनी लड़ाई का केंद्र बिंदु है, जो पिछले साल जून में व्यवसायी संजय कपूर के निधन के बाद उनके द्वारा छोड़ी गई 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर चल रही है। मुख्य विवाद संजय कपूर की मां से है।

परिवार के सभी सदस्य मध्यस्थता के लिए राजी

विवाद में शामिल परिवार के सभी सदस्य ट्रस्ट से जुड़े मामले में मध्यस्थता के लिए पेश होने को राजी हो गए हैं। इनमें संजय कपूर की दूसरी पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चे, समायरा और कियान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जालसाजी का उनका मामला ट्रस्ट से अलग चलेगा। उनकी तीसरी पत्नी, प्रिया कपूर ने अदालत से कहा कि उनके दिवंगत पति की मां यानी रानी कपूर को सार्वजनिक रूप से घर के झगड़े ज़ाहिर करना बंद कर देना चाहिए। उनका इशारा सार्वजनिक रूप से की जा रही टिप्पणियों की ओर था। इसके बाद न्यायालय ने मध्यस्थता की कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया।

अगली सुनवाई अब अगस्त में होगी

पीठ ने कहा, आज संबंधित पक्षों की ओर से पेश सभी वकीलों ने मध्यस्थता के लिए सहर्ष सहमति व्यक्त की है। इसे देखते हुए हम भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करते हैं। पीठ ने यह भी कहा, हम मध्यस्थ से प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद मामले में आगे की कार्यवाही करेंगे। मामले की अगली सुनवाई अब अगस्त में होगी।

पारिवारिक ट्रस्ट को अमान्य घोषित करने की मांग

शीर्ष अदालत ने 27 अप्रैल को, संजय कपूर की मां द्वारा दायर उस मामले में प्रिया कपूर और अन्य से जवाब मांगा था जिसमें पारिवारिक ट्रस्ट को अमान्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। पीठ ने 80 वर्षीय रानी कपूर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था।

कांग्रेस को भी मिला सालों से खोया हुआ ऑफिस

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को बुरी तरह पटखनी दे दी है। सत्ता पलट होने के साथ ही पूरे राज्य में आगजनी, तोड़फोड़ और झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल 9 मई को राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। उससे पहले बंगाल बीजेपी के बड़े नेता और संभावित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा मुर्शिदाबाद के जियागंज इलाके में भीड़ ने लेनिन की मूर्ति को तोड़ दिया। 24 परगना में टीएमसी नेता जहांगीर खान के ऑफिस में भी भीड़ ने तोड़फोड़ की है।

बंद मंदिर खुले, रोड से हट गए फर्जी टोल

वेस्ट बंगाल में दिखने लगा परिवर्तन का असर

कांग्रेस कार्यालयों से हटा कब्जा

चुनाव के नतीजे आते ही एक तरफ बीजेपी कार्यालय में मिठाइयां बंट रही थीं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के कई जिलों में कांग्रेस के कार्यालय ताला तोड़कर खोले गए। कांग्रेस के इन कार्यालयों को टीएमसी ने कब्जा रखा था। बीजेपी के सत्ता में आने के साथ ही कांग्रेस को उसके कार्यालय वापस मिल गए।

● **कई जिलों में मंदिरों में फिर शुरू हुई पूजा-** कई जिलों में मंदिरों पर भी ताले लटका दिए गए थे। जैसे ही प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, वैसे ही इन मंदिरों के ताले खोलकर इनमें साफ-सफाई शुरू कर दी गई। पूरे पश्चिम बंगाल से ऐसे कई वीडियो सामने आए, जिनसे सालों से दबी भावनाएं फिर मुखर होकर सामने आईं।

● **नाकों पर हो रही अवैध वसूली बंद-** पश्चिम बंगाल से लगी अन्य राज्यों की सीमाओं पर कहीं पुलिस तो कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता वाहनों से अवैध वसूली करते थे। सत्ता बदलते ही अब उन नाकों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कई जगहों से ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जहां पहले वाहनों से वसूली होती थी और अब उन नाकों से वाहन सीधे निकल रहे हैं। ऐसा शायद ही कभी देखा गया हो कि किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन को सरकारी कर्मचारी भी खुले तौर पर समर्थन कर रहे हों। पश्चिम बंगाल सचिवालय में चुनावी नतीजे साफ होते ही सभी कर्मचारी इकट्ठे हो गए और जमकर अपनी खुशी जाहिर की। यह कर्मचारी पिछले काफी वर्षों से सरकार से डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

कई सालों से दबी आह अब निकली

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक युवक बता रहा है कि लॉकडाउन के समय उससे स्थानीय टीएमसी नेता ने 5 लाख रुपए की मांग की थी। जिसे न देने पर उससे अंजाम भुगतने को तैयार रहने कहा गया। युवक ने जब वसूली देने से मना किया तो उसकी दुकान पर रोज कचरा फिंकवा कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसकी दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी भड़काया गया। सत्ता बदलते ही युवक ने वीडियो बनाकर अपनी भड़ास निकाली है। फिलहाल सभी को 9 मई का इंतजार है। शपथ ग्रहण के बाद सरकार संभालते ही कानूनी स्थिति भी संभलने की उम्मीद है। लोगों में बदलाव को लेकर सकारात्मकता देखी जा रही है। बता दें कि बीजेपी पहली बार अपने दम पर पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है।

राजगढ़ में एक ही मोहल्ले में 27 बच्चों को ब्लड कैंसर

सांसद रोडमल नागर के खुलासे से हड़कंप, बोले-पंजाब की राह पर राजगढ़

भोपाल। राजगढ़ जिले में खानपान की चीजों में मिलावट और खेती में रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने डरावनी शक्ल अख्तियार कर ली है। स्थानीय सांसद रोडमल नागर ने एक कार्यक्रम के दौरान जो आंकड़े पेश किए, उसने सबको चौंका दिया है। सांसद का दावा है कि उनके अपने निवास क्षेत्र (पचोर) की एक ही कॉलोनी में पिछले 3-4 सालों के भीतर 27 बच्चे ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारी की चपेट में आ गए हैं। सांसद नागर ने चेतावनी दी कि अगर मिलावट और केमिकल का यही हाल रहा, तो राजगढ़ जिला अगले 10 सालों में पंजाब बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब की जमीन को बर्बाद होने में 50 साल लगे, लेकिन हम जिस रफ्तार से यूरिया और कीटनाशक डाल रहे हैं, हमारी जमीन 10 साल में ही बंजर हो जाएगी।

लौकी में इंजेक्शन और मूंग दाल में जहर

सांसद ने मिलावटखोरी पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि आज सबसे पौष्टिक मानी जाने वाली सब्जियां और दालें भी जहरीली हो चुकी हैं। लौकी जैसी सेहतमंद सब्जी में भी इंजेक्शन लगाकर उसे बड़ा किया जा रहा है। पैदावार बढ़ाने के चक्कर में किसान एक बीघा जमीन में तीन-तीन बोरी यूरिया डाल रहे हैं। जो दाल बीमारों को ठीक करने के लिए दी जाती थी, आज वही मिलावट के कारण शरीर को नुकसान पहुंचा रही है।

नकली दूध वालों के खिलाफ जंग

सांसद ने जिले में सक्रिय नकली दूध के माफियाओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर कहीं भी सिंथेटिक या नकली दूध बन रहा है, तो उसकी सूचना तुरंत उन्हें, विधायक को या सीधे कलेक्टर-एसपी को दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। नागर ने कहा कि इस लड़ाई में समाज को सरकार का साथ देना ही होगा। सांसद के इस इमोशनल बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर हालात इतने खराब हैं, तो सांसद ने संसद में अब तक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्यों नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि जनता ने आपको संसद में अपनी आवाज उठाने के लिए भेजा है, सिर्फ भावुक भाषण देकर आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते।

भोजशाला विवाद में अब जैन समाज की एंट्री

हिंदू-मुस्लिम के बाद जैनों ने ठोंका दावा, कहा-यह हमारा गुरुकुल

भोपाल। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर को लेकर चल रही कानूनी जंग में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। अब तक यह विवाद मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच था, लेकिन अब जैन समाज ने भी इस पर अपना दावा पेश किया है। इंदौर हाईकोर्ट की बेंच के सामने याचिकाकर्ता सालेक चंद जैन की ओर से दलील दी गई कि इस स्मारक का गहरा संबंध जैन परंपराओं से भी है।

वाग्देवी नहीं, जैन यक्षिणी अंबिका की मूर्ति- जैन समाज की ओर से पेश वकील दिनेश राजभर ने हाईकोर्ट में सबसे बड़ा तर्क 'वाग्देवी' की उस मूर्ति को लेकर दिया, जो फिलहाल लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में है। हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती की प्रतिमा बताता है, लेकिन जैन पक्ष का दावा है कि यह असल में जैन यक्षिणी अंबिका की मूर्ति है। राजभर ने तर्क दिया कि मूर्ति पर बने नक्काशीदार तीर्थंकरों के चित्र स्पष्ट रूप से जैन प्रतिमा विज्ञान का हिस्सा हैं, जो सरस्वती की हिंदू प्रतिमाओं में नहीं पाए जाते। उन्होंने कहा, 'चूंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों को माना जाता है, इसलिए उनके चिन्ह जैन देवी-देवताओं की मूर्तियों पर मिलते हैं।' याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के साल 2003 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत वर्तमान में व्यवस्था चल रही है। फिलहाल मंगलवार- हिंदुओं को पूजा और बसंत पंचमी पर विशेष आयोजन की अनुमति है। शुक्रवारः मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने की इजाजत है। जैन पक्ष का कहना है कि जब इस स्थल का ऐतिहासिक संबंध जैन धर्म से भी है, तो उन्हें पूजा के अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया है।

भोपाल में इंजीनियरिंग छात्र ने छात्रा से किया रेप

इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद वारदात को अंजाम दिया, पुलिस जांच में जुटी

भोपाल। भोपाल के पिपलानी इलाके में इंजीनियरिंग के छात्र ने एक छात्रा के साथ रेप किया। आरोपी ने पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी। मुलाकात के बहाने उसे एक रूम पर ले गया। जहां उसने युवती को डरा-धमकाकर रेप किया। बुधवार रात पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सब इंस्पेक्टर आनंद सिंह परिहार के मुताबिक 22 वर्षीय युवती एक निजी कॉलेज की छात्रा है। करीब एक महीने पहले उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से इंजीनियरिंग करने वाले आयुष पसथारिया से हुई थी। पहले दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई और मामला प्रेम प्रसंग तक पहुंच गया। इसके बाद अप्रैल महीने उसे बहला-फुसलाकर अपने किराए के रूम पर ले गया। जहां उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। उसके बाद से वह लगातार पीड़िता का शोषण कर रहा था। उसकी करतूतों से परेशान होकर पीड़िता बुधवार की दोपहर को थाने पहुंची और आरोपी युवक पर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात एफआईआर दर्ज कर ली।

मुख्यमंत्री यादव ने आरकेएमपी स्टेशन से दिखाई हरी झंडी

'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा' राजधानी भोपाल से रवाना

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारने की घटना की निंदा करते हुए गुरुवार को कहा कि चुनाव में हार-जीत चलती रहती है। केवल चुनाव हार जाने के कारण हिंसा पर उतर आना गलत है। जनता ने इसी वजह से आपको घर बैठाया है। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसके पहले मुख्यमंत्री ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म-एक से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा' को रवाना किया। पहली बार आयोजित की जा रही इस यात्रा में 1100 श्रद्धालु जा रहे हैं। संस्कृति विभाग यह गौरवशाली यात्रा 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के अंतर्गत निकाल रहा है। कार्यक्रम में विधायक रामेश्वरम शर्मा, भगवान दास सबनानी, भाजपा प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर देश के दुश्मनों को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत की ओर कोई भी विदेशी ताकत बुरी नजर डालेगी, तो उसे करारा जवाब मिलेगा। यह नया भारत है, जो अपने दुश्मनों से निपटना अच्छी तरह जानता है। हाल ही में हुए हमले का भी देश ने मजबूती से जवाब दिया है।

सुविधाएं बढ़ीं तो बढ़ गए श्रद्धालु- मुख्यमंत्री ने उज्जैन में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि देवलोक बनने से बदल जाती है अर्थव्यवस्था। उन्होंने कहा 2022 से पहले उज्जैन में रोजाना सिर्फ 25 से 30 हजार श्रद्धालु आते थे, लेकिन अब प्रतिदिन डेढ़ लाख से ज्यादा लोग बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सोमनाथ मंदिर पर इतिहास में 17 बार आक्रमण हुए, लेकिन आज भी हजार साल बाद सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ खड़ा है और आस्था का प्रतीक बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मध्यप्रदेश सरकार निरंतर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हमने राज्य में हेली सेवा प्रारंभ की, जिससे धार्मिक स्थलों तक पहुंच और अधिक सरल हुई है। इसी क्रम में अब रेलवे के माध्यम से 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026' की शुरुआत की गई है। हमारी सरकार सनातन संस्कृति के संरक्षण और उत्थान के लिए योजनाबद्ध तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आज दुनिया अलग दौर में पहुंच चुकी है, लेकिन भारतीय संस्कृति हमेशा 'जियो और जीने दो' का संदेश देती है। यह पूरी मानवता के कल्याण की संस्कृति है। महादेव के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव बना रहे। उन्होंने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान भगवान की भक्ति का पूरा आनंद लें और सत्संग में भी हिस्सा लें। इसलिए निकाली जा रही यात्रा भारत की सांस्कृतिक चेतना, आस्था और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व-2026 (8 से 11 जनवरी 2026) का शुभारंभ ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर से किया गया। इसमें प्रदेश के लोग भी शामिल हो रहे हैं। यह पहली यात्रा प्रदेश से पहली बार निकलने वाली इस विशेष यात्रा में विभिन्न अंचलों से 1100 श्रद्धालुओं का दल शामिल हैं। यह ट्रेन भोपाल और उज्जैन रेलवे स्टेशनों से भी तीर्थयात्रियों को अपने साथ लेकर सोमनाथ जा रही है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु सोमनाथ की पावन धरा पर आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, दर्शन और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता करेंगे।

आदर्श जिला बनाने के लिए सभी समन्वयक रुप से प्रयास करें

मध्यप्रदेश सरकार समग्र विकास के लिए संकल्पित, जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक संपन्न

भोपाल। आदर्श जिला बनाने के लिए सभी समन्वयक रूप से प्रयास करें, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्माण कार्यों का भूमिपूजन, लोकार्पण करें। मध्यप्रदेश सरकार समग्र विकास के लिए संकल्पित है। सागर रिंग रोड, बायपास का कार्य शीघ्रता से करें, साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य तत्काल शुरू करें। उक्त विचार उप मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सागर में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में व्यक्त किए। इस अवसर पर विधायक एवं पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह, विधायक शैलेन्द्र जैन, विधायक प्रदीप लारिया, विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया, विधायक श्रीमती निर्मला सप्रे, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, महापौर श्रीमती संगीता तिवारी, जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, जिला पंचायत सीईओ विवेक केवी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बैठक में निर्देश दिए कि सागर को आदर्श जिला बनाने के लिए सभी समन्वयक रूप से कार्य करें। स्मार्ट सिटी के माध्यम से सागर में अन्य शहरों की अपेक्षा बहुत अच्छे कार्य हुए है। जिससे सागर अपनी नयी पहचान बनाने में सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि सागर शहर को जोड़ने वाले रिंग रोड एवं भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर को जोड़ने वाले वाईपास का कार्य शीघ्र गति से पूरा करें जिससे जिलेवासियों के साथ अन्य व्यक्तियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि बीना रिफाईनरी के परिक्षेत्र में सड़कों का निरीक्षण करें एवं मरम्मत के लिए डीपीआर तैयार कराएं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सड़क के प्रस्ताव विधानसभावार तैयार कर सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की स्वीकृति भूमिपूजन, लोकापर्ण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से सागर में विधायक भूपेन्द्र सिंह, विधायक शैलेन्द्र जैन के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं जिसके माध्यम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की परिकल्पना पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि सागर नगर की ट्राफिक व्यवस्था सुधारने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्टिंग का कार्य एवं राजघाट चौराहे से धर्मतक सड़कों से खंभे हटाने का कार्य शीघ्र गति से करें।

विधायक एवं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ब्लड बैंक की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। जिस पर उप मुख्यमंत्री शुक्ल द्वारा जिला चिकित्सालय से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को ब्लड बैंक हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए एवं ब्लड बैंक को अत्यधिक सर्व सुविधायुक्त बनाने के साथ ही ब्लड बैंक की प्रारंभ में 2000 यूनिट और भविष्य में 5000 यूनिट तक बढ़ाने के संबंध में कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि संभाग वासियों के हित के दृष्टिगत इस ब्लड बैंक में अत्याधुनिक सुविधाओं जैसे ए एन टी टेस्टिंग, प्लाजमा थेरेपी, सिंगल डोनर आदि सभी प्रकार के कार्य किये जा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि स्टोर क्षमता बढ़ने से आवश्यकता वाले व्यक्तियों को आसानी से ब्लड मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं जहां 1500 से 2000 यूनिट रक्त एकत्रित होता है जिसको जिले से अन्यत्र भी भेजा जाता है जिससे जिलेवासियों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता, क्षमता बढ़ने से जिलेवासियों को इसका लाभ मिल सकेगा।

विधायक शैलेन्द्र जैन ने लेहदरा नाका से बेरखेड़ी गुरु तक प्रस्तावित बाईपास निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने धर्मसे भोपाल रोड तक प्रस्तावित धर्मबाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण का विषय प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि अधिकांश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के शेष निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा करते हुए उन्हें समयसीमा में पूर्ण कराने पर जोर दिया। फर्नीचर क्लस्टर की कार्य प्रगति की जानकारी ली तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान सागर में हुए एमओयू की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने सागर के उत्कृष्ट विद्यालय का नाम शहीद प्रदीप लारिया के नाम पर रखने तथा विद्यालय परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग भी की।

हिंदू कैदी पर आया मुस्लिम लेडी जेल अफसर का दिल

उम्रकैद की सजा के बाद की शादी, विश्व हिंदू परिषद के नेता ने किया कन्यादान

भोपाल। सतना सेंट्रल जेल की सहायक अधीक्षक फिरोजा खातून ने हत्या के मामले में सजा काट चुके धर्मेंद्र (अभिलाष) नाम के युवक से हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली। 5 मई को छतरपुर जिले के लवकुश नगर में हुए इस विवाह की पूरे इलाके में चर्चा है। अभिलाष उम्रकैद की सजा काट चुका है और करीब 4 साल पहले जेल से रिहा हुआ था। बताया जा रहा है कि फिरोजा के मुस्लिम परिजन इस रिश्ते से नाराज थे। वे शादी में शामिल नहीं हुए। ऐसे में सतना विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष राजबहादुर मिश्रा ने सपत्नीक माता-पिता के रूप में कन्यादान कराया। इस दौरान बजरंग दल के लोग भी मौजूद थे।

जेल में वारंट के काम के दौरान हुई थी मुलाकात- जानकारी के मुताबिक, सतना जेल में पदस्थापना के दौरान फिरोजा खातून वारंट इंचार्ज का काम संभाल रही थीं। उसी दौरान हत्या के मामले में सजा काट रहा अभिलाष भी जेल के भीतर वारंट संबंधी काम करता था। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्रेम संबंध में बदल गई। अभिलाष के जेल से रिहा होने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया।

2007 के चर्चित हत्याकांड में मिली थी उम्रकैद

अभिलाष छतरपुर जिले के चंदला का रहने वाला है। वर्ष 2007 में चंदला नगर परिषद के तत्कालीन उपाध्यक्ष कृष्णदत्त दीक्षित की हत्या कर शव जमीन में दफनाने के मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। करीब 14 साल जेल में रहने के बाद अच्छे आचरण के आधार पर उसे रिहा कर दिया गया था।

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ विवाह

लवकुश नगर में दोनों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार से हुआ। शादी की खबर सामने आने के बाद सतना जेल के अधिकारियों, कर्मचारियों और कैदियों ने भी नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं। यह शादी इलाके में प्रेम, सामाजिक बंधनों और धर्म से ऊपर उठकर लिए गए फैसले को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है।

सीएम हाउस में करेंगे तालाबंदी इंदौर हाईवे पर चक्काजाम

प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले-पंचायत स्तर पर करेंगे आंदोलन

भोपाल। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को आगरा-मुंबई हाईवे पर खलघाट से लेकर मुरैना तक करीब 580 किलोमीटर के दायरे में 7 जगहों पर हाईवे जाम किया। कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की और नोकझोंक हुई, जबकि हजारों यात्री घंटों फंसे रहे। शाजापुर के रोजवास टोल प्लाजा, ग्वालियर के निरावली तिराहे, इंदौर बायपास, महू और मुरैना सहित कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस आंदोलन को किसानों की आवाज बताया, तो भाजपा ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कहा कि कांग्रेस ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया था। तय समय पूरा होते ही किसान और कार्यकर्ता सड़क से हट गए। उन्होंने कहा- अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी, तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर तालाबंदी की जाएगी।

किसान सड़क पर फसल फेंक रहा, सरकार झालमुड़ी खा रही- खलघाट टोल टैक्स पर चक्काजाम खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश का किसान अपनी फसल सड़क पर फेंकने को मजबूर है, लेकिन सरकार कुंभकरण की नींद में सो रही है। अगर सरकार को सिर्फ बंगाल की राजनीति करनी है, तो मुख्यमंत्री वहीं चले जाएं, फिर मध्य प्रदेश में उनका क्या काम है। सिंघार ने कहा कि किसान सब देख रहा है और अगर सरकार किसानों को रुलाएगी तो किसान भी सरकार को रुलाने का काम करेंगे। इस समय पूरी बीजेपी 'झालमुड़ी खाने' में व्यस्त है। पश्चिम बंगाल की राजनीति दिखाई दे रही है, लेकिन किसानों का गेहूं और सोयाबीन दिखाई नहीं दे रहा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जिस दिन 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, उसी दिन चक्काजाम करना गैरजिम्मेदाराना है। अगर कांग्रेस थोड़ी समझदारी दिखाती तो बच्चों की परेशानी समझती। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा देने जा रहे छात्र प्रभावित हुए हैं और इसका श्राप कांग्रेस के माथे पर लगेगा।

प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। शाजापुर के रोजवास टोल प्लाजा, ग्वालियर के निरावली तिराहे, इंदौर बायपास, महू और मुरैना समेत कई जगहों पर सुबह से कार्यकर्ता जुटने लगे थे।

जनगणना में गलत जानकारी दी तो होगी मुश्किल

टीम को अंदर आने से रोका तो होगी जेल और जुर्माना

भोपाल। साल 2027 की जनगणना के पहले चरण यानी 'हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन्स' का काम शुरू हो गया है। इस दौरान जनगणना कर्मचारी आपके घर आकर जानकारी जुटाएंगे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जनगणना के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देना हर नागरिक की कानूनी जिम्मेदारी है। अगर कोई जानबूझकर गलत जानकारी देता है या टीम को सहयोग नहीं करता, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। भोपाल जिले में इस काम के लिए करीब 6,000 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये कर्मचारी इस महीने से लेकर 30 मई तक घर-घर जाकर डेटा इकट्ठा करेंगे। इस पहले फेज में मुख्य रूप से मकानों की लिस्टिंग और उनसे जुड़ी बुनियादी जानकारी ली जाएगी। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 33 सामान्य सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जवाब देना अनिवार्य है।

नियम तोड़ने पर जेल और जुर्माना दोनों

जनगणना नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति सवालों के जवाब देने से मना करता है, गलत तथ्य बताता है या किसी कॉलोनी/कैंपस में कर्मचारी को घुसने से रोकता है, तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में सजा का प्रावधान और भी कड़ा है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जनगणना नियमों का उल्लंघन करने पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति जनगणना दफ्तर में अनाधिकृत तरीके से घुसता है, तो उस पर जुर्माना और सजा दोनों की तलवार लटक सकती है।

सांस्कृतिक परंपराओं का रखा जाएगा ध्यान

नियम कड़े जरूर हैं, लेकिन भारत की सांस्कृतिक विविधताओं का इसमें पूरा ख्याल रखा गया है। अगर किसी परिवार की परंपरा में महिला सदस्य या पति का नाम लेना वर्जित है, तो उन्हें नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थितियों में प्रशासन छूट देगा। अक्सर लोगों के मन में डर होता है कि उनकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना में दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहती है। इस डेटा को किसी भी दीवानी या आपराधिक कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहां तक कि किसी को भी जनगणना से जुड़े रजिस्टर या रिकॉर्ड देखने की अनुमति नहीं होती है। भोपाल के लोग यह जानने को भी उत्सुक हैं कि जातिगत आंकड़े कब लिए जाएंगे। बता दें कि जाति की गणना जनगणना 2027 के दूसरे और अंतिम चरण में होगी। यह काम फरवरी 2027 में किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन का पूरा जोर पहले चरण को शांतिपूर्वक पूरा करने पर है।

संपादकीय

यह तो शुभेंदु अधिकारी को चुनौती !

पश्चिम बंगाल में भारी सुरक्षा व्यवस्था के चलते विधानसभा चुनाव के दौरान भले ज्यादा हिंसा न हुई हो, लेकिन नतीजे घोषित होने के बाद वहां जिस तरह खुलेआम हत्याएं और आगजनी हो रही है, वह नई सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वह बंगाल के इस ‘रक्त चरित्र’ को कैसे बदल पाती है। हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनियों के बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली प्रदेश के संभावित मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की दिनदहाड़े सुनियोजित हत्या सीधे-सीधे नई सत्ता को अपराधियों की खुली चुनौती है। वहां नई सरकार अभी बनी भी नहीं है कि अपराधी बेखौफ होकर अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ भवानीपुर चुनाव में उनके प्रभारी थे। उन्हें परसों रात नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यरम ग्राम में घेर कर 4 गोलियां मारी गईं। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या से पहले रथ स्कॉर्पियो से अपने घर की ओर जा रहे थे। इस घटना से न केवल बंगाल बल्कि सारा देश स्तब्ध रह गया है। विपक्षी तृणमूल कांग्रेस ने घटना की निंदा करते हुए न्यायाधीश की निगरानी में इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि भाजपा नेताओं और मृतक की मां का आरोप है कि इस हत्या के पीछे तृणमूल कांग्रेस का ही हाथ है। भाजपा विधायक अर्जुनसिंह ने सीधे ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर इस हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगाया है। इस घटना को जिसने भी और जिस किसी के इशारे पर अंजाम दिया, वह एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि हमले का असल मकसद स्वयं शुभेंदु अधिकारी थे, लेकिन वो गाड़ी में नहीं होने से बच गए। इस हमले में रथ का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हत्यारों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने इसे प्लान्ड मर्डर बताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि भाजपा बंगाल में गुंडों की सफाई का काम शुरू करेगी। इस बीच पुलिस ने एक आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आशंका है कि इस हत्याकांड के पीछे बांगलादेशी लोगों का भी हाथ हो सकता है। उधर पुलिस ने घटनास्थल से जिंदा कारतूस और खाली खोखे बरामद किए गए। स्कॉर्पियो का रास्ता रोकने वाली कार भी जब्त की गई। इस हत्याकांड के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने NH 12 पर जाम लगाया। हमलावरों के एनकाउंटर की मांग की गई। इससे घटना के करीब 1 घंटे बाद रात करीब 12.30 बजे बशीरहाट जिले में रोहित रॉय नाम के भाजपा कार्यकर्ता पर भी फायरिंग हुई। उनकी हालत गंभीर है। गौरतलब है कि राज्य में 4 मई को चुनावी नतीजों के बाद अब तक 5 लोगों की हत्या हो चुकी है। इनमें 3 भाजपा और 2 TMC से जुड़े थे। पूर्व वायु सैनिक रहे रथ हाल के वर्षों में शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक कार्यों में पृष्ठभूमि में रहने वाले प्रमुख व्यक्ति के तौर पर उभरे। उन्होंने संगठनात्मक कार्य का देखा, लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संचार बनाए रखा। रथ भाजपा के भवानीपुर अभियान सहित कई हाई-वोल्टेज राजनीतिक लड़ाइयों के दौरान कोर टीम का भी हिस्सा थे। अटकलें भी थीं कि रथ को एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उनकी हत्या ने बंगाल में पहले से ही अस्थिर माहौल को और भड़का दिया है। बंगाल को इस खूनी चरित्र से मुक्त करना होगा।

महिलाओं की राजनीति में भूमिका प्रतीक या निर्णायक

नजरिया

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

लेखक स्तंभकार हैं।

हाल के महीनों में देश की राजनीति में एक बार फिर महिलाओं की भागीदारी का प्रश्न तेज़ी से उभरा है। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि अब राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल वादों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ज़मीन पर भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन जैसे-जैसे विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आए, एक कड़वी सच्चाई भी उजागर हुई, राजनीतिक दलों के दावे और वास्तविकता के बीच गहरी खाई अब भी कायम है। टिकट वितरण में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही और जीतकर आने वाली महिलाओं की संख्या तो और भी कम दिखाई दी। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या हमारे लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी सचमुच प्राथमिकता है या फिर यह केवल राजनीतिक विमर्श का एक आकर्षक विषय भर बनकर रह गया है।

भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद समानता और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर टिकी है। संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में यह समानता आज भी अधूरी है। वर्षों से यह कहा जाता रहा है कि महिलाएं समाज की आधी आबादी हैं, इसलिए उन्हें राजनीति में भी समान भागीदारी मिलनी चाहिए। संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण की मांग भी इसी विचार से प्रेरित रही है। लेकिन जब चुनाव आते हैं, तब यही सिद्धांत अक्सर राजनीतिक समीकरणों के आगे बौना पड़ जाता है। दलों की प्राथमिकता जीतने योग्य उम्मीदवार होती है, और इस कसौटी पर महिलाएं अक्सर पीछे धकेल दी जाती हैं।

यदि हालिया विधानसभा चुनावों पर नज़र डालें, तो यह स्पष्ट होता है कि लगभग सभी प्रमुख दलों ने महिलाओं को टिकट देने के मामले में अपेक्षित उदारता नहीं दिखाई। कई राज्यों में कुल उम्मीदवारों की संख्या की तुलना में महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत बेहद कम रहा। यह स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब यह देखा जाता है कि जो महिलाएं मैदान में उतरीं, उनमें से भी बहुत कम जीत हासिल कर सकीं। इसका एक कारण यह भी है कि कई बार महिलाओं को ऐसे क्षेत्रों से टिकट दिया जाता है जहां पार्टी की स्थिति पहले से कमजोर होती है, जिससे उनकी जीत की संभावना स्वतः कम हो जाती है।

राजनीतिक दलों के इस व्यवहार के पीछे कई परतें हैं। पहली परत है सामाजिक संरचना की, जहां अब भी यह धारणा गहरी जड़ें जमाए हुए है कि राजनीति पुरुषों का क्षेत्र है। महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में स्वीकार करने में समाज को समय लग रहा है। दूसरी परत है दलों के भीतर की सत्ता

संरचना, जहां निर्णय लेने वाले अधिकांश लोग पुरुष हैं। ऐसे में महिलाओं को टिकट देने का निर्णय भी उन्हीं की सोच और प्राथमिकताओं से प्रभावित होता है। तीसरी परत है संसाधनों की, क्योंकि चुनाव लड़ना महंगा और संसाधन-सघन प्रक्रिया है। महिलाओं के पास अक्सर वह आर्थिक और राजनीतिक समर्थन नहीं होता जो पुरुष उम्मीदवारों को सहज उपलब्ध होता है।

हालांकि यह तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। कुछ राज्यों और कुछ दलों ने महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक अवसर देने की कोशिश की है। स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण ने एक नई पीढ़ी की महिला नेताओं को जन्म दिया है, जिन्होंने अपनी क्षमता और नेतृत्व कौशल से यह साबित किया है कि अवसर मिलने पर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहतीं। पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने यह संकेत दिया है कि यदि उन्हें मंच मिले, तो वे न केवल प्रभावी प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, बल्कि विकास के नए आयाम भी स्थापित कर सकती हैं।

फिर भी, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में यह बदलाव धीमी गति से ही आगे बढ़ रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि यहां प्रतिस्पर्धा अधिक तीव्र है और दांव भी बड़े होते हैं। दल अक्सर जोखिम लेने से बचते हैं और परंपरागत उम्मीदवारों पर ही भरोसा जताते हैं। लेकिन यह सोच लंबे समय में लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। जब आधी आबादी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तो नीतियों और निर्णयों में भी उनका दृष्टिकोण पूरी तरह शामिल नहीं हो पाता। इससे विकास असंतुलित हो जाता है और समाज के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं।

महिला आरक्षण विधेयक को इसी असंतुलन को दूर करने के एक बड़े कदम के रूप में देखा गया था। यह विधेयक केवल सीटों का आरक्षण नहीं, बल्कि एक मानसिक बदलाव की दिशा में प्रयास भी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को राजनीति में प्रवेश के लिए एक न्यूनतम आधार मिले, जिससे वे अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। लेकिन केवल कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं होता। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक समर्थन दोनों की आवश्यकता होती है।

राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि महिलाओं को टिकट देना कोई दया या कृपा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। उन्हें अपने संगठनात्मक ढांचे में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी, ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी आवाज़ शामिल हो सके। साथ ही, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, संसाधन और नेटवर्किंग के अवसर भी बढ़ाने होंगे, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतर सकें। समाज की भूमिका भी इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। जब तक मतदाता महिलाओं को एक सक्षम नेता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक दल भी उन्हें प्राथमिकता देने से हिचकते रहेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाएं और महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करें। मीडिया और शिक्षा प्रणाली भी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे जनमत निर्माण के शक्तिशाली माध्यम हैं।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का प्रश्न केवल प्रतिनिधित्व का नहीं, बल्कि न्याय और समानता का प्रश्न है। यह हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि हम वास्तव में एक समावेशी और संतुलित समाज की कल्पना करते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं को राजनीति में बराबरी का स्थान मिले। इसके लिए केवल नीतिगत बदलाव ही नहीं, बल्कि मानसिकता में परिवर्तन भी आवश्यक है। आज जब देश तेजी से बदल रहा है और नए-नए आयामों को छू रहा है, तब यह और भी जरूरी हो जाता है कि राजनीति भी इस बदलाव के साथ कदम मिलाकर चले। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक राजनीतिक अनिवार्यता भी है। यदि हम इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करें, तो वह दिन दूर नहीं जब भारतीय राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि निर्णायक होगी।

पांच राज्यों के जनादेश का क्या है दिशा संकेत?

राजनीति

राजीव खंडेलवाल

(लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, बैतूल सुधार न्यास)

जैसे ‘पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती’, उसी प्रकार हाल ही में संपन्न पांच राज्यों के चुनाव भी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक दृष्टि से एक-दूसरे से भिन्न रहे। ऐसे में सभी राज्यों के परिणामों को ‘एक ही तराजू में तौलना’ न तो उचित है, न ही वैज्ञानिक। पिछले लेख में प्रस्तुत मेरा आकलन पूर्णतः सही सिद्ध नहीं हुआ–इसके लिए मैं पाठकों से क्षमा प्रार्थी हूं। किंतु इन चुनावों में पिछले चुनावों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत, क्षेत्रीय विस्तार और प्रभाव में वृद्धि का मेरा आकलन सही सिद्ध हुआ।

इन चुनावों ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि ‘एग्जिट पोल’ कुछ ‘संकेत’ तो दे सकते हैं, परंतु पूर्णरूप ‘सत्य’ नहीं होते हैं। सबसे बड़ा ‘उलटफेर’ तमिलनाडु में हुआ, जहां सुपर स्टार ‘थलपति विजय’ की मात्र 2 वर्ष 2 माह पूर्व गठित नई पार्टी तमिलगा वेत्री कडगम (टीवीके) पहले ही चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर विजय नाम को सार्थक कर दिया। टीवीके का अर्थ ‘तमिलों का विजय संगठन’ है। आगे कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनाने की भी पूरी संभावना है। ‘सर्वे’ करने वाली समस्त एजेंसियों में से सबसे अधिक व सफल परिणाम देने वाली प्रतिष्ठित एक्सिस माई इंडिया ने ही 98 से 120 सीट मिलने का अनुमान दिया था। इसके पूर्व विजय से भी बड़े प्रसिद्ध फिल्मी कलाकार कमल हासन व रजनीकांत चुनावी राजनीति में असफल हो चुके हैं।

असम आंदोलन प्रणेता ‘आसु’ द्वारा स्थापित असम गण परिषद (अगप) ने अक्टूबर 1985 में गठन के मात्र 2 महीने के अंदर असम में सबसे तेज बहुमत से पहली बार क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनाकर विश्व में एक तरह का नया रिकॉर्ड बनाया था। इसके पूर्व वर्ष 1982 में आंध्र प्रदेश के फिल्मी स्टार एन टी रामाराव द्वारा नई पार्टी बनाने के बाद मात्र 9 महीने में विधानसभा चुनाव में उतर कर 294 में से 201 सीटें प्राप्त कर भारी बहुमत से जीत प्राप्त की थी। तमिलनाडु में एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरती ताकत टीवीके ने पारंपरिक राजनीति को सफल चुनौती दी।

पश्चिम बंगाल: राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से पश्चिम बंगाल के परिणाम सबसे अधिक चर्चा में रहकर महत्वपूर्ण हैं। यहां मुकाबला वैचारिक, संगठनात्मक और नेतृत्व–तीनों स्तरों पर कड़ा था। भाजपा ने जहां सर्वाधिक पूरी ताकत झोंक दी, वहीं ममता बनर्जी ने भी उतनी ही पूरी शक्ति के साथ सामना किया। परंतु परिणाम पिछले चुनाव की तुलना में बिल्कुल उलट आए (207-80) जो अमूमन लगभग एग्जिट पोल के अनुसार ही आये। ममता दीदी को अपने नाम के अनुरूप ममत्व दिखाते हुए परिणाम को स्वीकार कर हार को गले लगा लेना चाहिए।

केरल: देश की सबसे अधिक पढ़ी-लिखी जनसंख्या तथा सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा देने वाला राज्य केरल में परंपरागत रूप से कांग्रेस और वामपंथ के बीच सीधा मुकाबला था। इसमें कांग्रेसनीत यूडीएफ की विजय पार्टी के लिए भले ही ‘संजीवनी बूटी’ हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पुनरुत्थान के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

इन परिणामों का स्पष्ट संदेश एक यह निकलता है, जहां कांग्रेस से भाजपा की सीधी लड़ाई है, वहां बीजेपी जीतती है। ऐसे प्रदेश असम व पुदुचेरी में कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। परिणाम समग्र रूप से यह भी दर्शाते हैं कि भारतीय राजनीति में ‘वन साइज फिट्स ऑल’ का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इस चुनाव ने कई ‘मिथकों’ को तोड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाएं चुनावी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं। परंतु वही फार्मूला दिल्ली में केजरीवाल के द्वारा अपनाने के बावजूद वे पिछले चुनाव में असफल रहे और अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी हार गई। मतलब साफ है, राष्ट्रीय स्तर पर कई मामले मामलों में भाजपा सरकार द्वारा वादा पूरा न कर पाने के बावजूद प्रदेश स्तर पर भाजपा के वादे पर जनता ज्यादा विश्वास कर कर उसे सत्ता पर पहुंचाती है। यह समस्त विपक्षियों के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए।

बंगाल में 2021 के चुनाव में 58 हत्याएं और 278 हिंसक घटनाओं की तुलना में शून्य मृत्यु और कुछ दर्जन छिटपुट घटनाएं होना इस बात को सिद्ध करता है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए। लोकतंत्र में ‘भयमुक्त मतदान’ आवश्यक शर्त है। तथापि कुछ मूर्धन्य पत्रकारों का यह कहना कि ममता के आतंक को केंद्र के अर्ध सैनिक बलों के आतंक ने ‘प्रतिस्थापित’ कर दिया।

यह बहस जारी है कि चुनावों में ध्रुवीकरण कितना प्रभावी रहा। योगी आदित्यनाथ की बंगाल में 35 विधानसभा क्षेत्र में हुई सभा में भाजपा को पश्यति से सफलता प्राप्त की है यह भी भगवा आंधी का एक उदाहरण है।

जीत का उन्माद, हार की निराशा।

लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि

जीत स्थायी नहीं होती,हार अंतिम नहीं होती।

जनादेश किसी एक दल की विजय भर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सामूहिक सफलता है।

विजेताओं को विनम्रता अपनानी चाहिए। पराजितों को आत्ममंथन करना चाहिए।

ऐतिहासिक विजय के लिए प्रधानमंत्री मोदी व उनके सफल नेतृत्व को हार्दिक इन बधाइयों से 27 लाख मतदाताओं को अलग करने के लिए मैं मजबूर हूं। क्योंकि जिनके मताधिकार उच्चतम न्यायालय ने छीने उनका कोई दोष सिद्ध नहीं था। लेकिन इसके विरुद्ध उन्होंने अपने संवैधानिक मताधिकार की प्राप्ति के लिए कोई गांधीवादी जन आंदोलन नहीं किया।

यदि राजनीतिक विजय को ‘गंगोत्री से गंगासागर तक विस्तार’ मान भी लें, तो भी मूल प्रश्न बना रहता है–कि क्या इससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी, न्यायपूर्ण और जनहितकारी बनी है?

रक्त की बूंद से जीवन तक की यात्रा

विश्व रेडक्रॉस दिवस पर विशेष

योगेश कुमार गोयल

लेखक पत्रकार हैं।

वर्ष 1864 में जीन हेनरी डयूनेंट के सतत प्रयासों के चलते जेनेवा समझौते के तहत ‘अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस मूवमेंट’ की स्थापना हुई थी। मानव सेवा के लिए हेनरी डयूनेंट को वर्ष 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। 8 मई 1828 को जेनेवा में जन्मे डयूनेंट एक स्विस व्यापारी तथा समाजसेवक थे, जो 1859 में हुई सालफिरोनो (इटली) की लड़ाई में घायल सैनिकों की दुर्दशा और रक्तपात का भयानक मंजर देखकर बहुत आहत हुए थे क्योंकि युद्धभूमि में पड़े इन घायल सैनिकों के उपचार के लिए कोई चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। युद्ध मैदान में पड़े हृदयविदारक कष्टों से तड़पते इन्हीं सैनिकों के दर्दनाक हालातों पर अपने कड़वे अनुभवों के आधार पर उन्होंने ‘मेमोरी और सालफिरोनो’ पुस्तक भी लिखी और 1863 में रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ‘आईसीआरआई’ का गठन किया। युद्धभूमि में घायलों की सहायता के लिए उन्होंने स्थायी समितियों के निर्माण की आवश्यकता को लेकर आवाज बुलंद की, जिसका असर भी दिखा।

युद्ध में आहतों की स्थिति के सुधार के साधनों का अध्ययन करने के लिए हेनरी डयूनेंट के ही प्रयासों से एक आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य जनरल डूफोर, स्विस सेना के सेनापति गस्टवे मोइनिए, हेनरी डयूनेंट, डॉ. लुई एपिया तथा डा. थियोडोर मोनोइ थे। जेनेवा में 26 से 29 अक्टूबर 1863 तक एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई, जिसमें रेडक्रॉस के आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किए गए तथा रेडक्रॉस आन्दोलन का विकास करते हुए आहत सैनिकों और युद्ध पीड़ितों की सहायता संगठित करने हेतु दुनियाभर के सभी देशों में राष्ट्रीय समितियां बनाने पर जोर दिया गया। 8 अगस्त 1864 को हुए जेनेवा अधिवेशन में सुरक्षा के प्रतीक रेडक्रॉस वाले सफेद झंडे पर स्वीकृति की मोहर लगाई गई, जो आज समस्त विश्व में रेडक्रॉस का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। जेनेवा अधिवेशन में कुछ ऐसे सिद्धांतों पर भी मोहर लगी, जिन्हें आज सभी देश स्वीकारते हैं। मसलन, युद्ध में आहतों का सम्मान होना चाहिए, सैनिक तटस्थ समझे जाने चाहिएं, चिकित्सा सेवाओं की सामग्रियों तथा कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए।

1863 में हुई रेडक्रॉस की स्थापना में चूंकि महान् मानवता प्रेमी हेनरी डयूनेंट का सबसे बड़ा योगदान था, इसीलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर ही प्रतिवर्ष विश्वभर में 8 मई का दिन ‘अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। ‘रेडक्रॉस’ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के अलावा आकस्मिक दुर्घटनाओं में घायलों, रोगियों, आपातकाल तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करती है। मानव सेवा को समर्पित रेडक्रॉस के उल्लेखनीय कार्यों की बदौलत इस संस्था को वर्ष 1917 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। रेडक्रॉस को अब तक कुल तीन बार 1917, 1944 तथा 1963 में शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। रेडक्रॉस ने प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अनेक घायल सैनिकों तथा नागरिकों की सहायता कर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया था। 1914 के प्रथम विश्वयुद्ध के समय रेडक्रॉस के करीब दो हजार स्वयंसेवकों ने न केवल विभिन्न सेनाओं तथा जहाजी बेड़ों के हजारों लापता सैनिकों का पता लगाया बल्कि 500 विभिन्न बंदी-शिविरों की नियमित देखरेख करते हुए हजारों युद्धबंदियों को सहायता भी मुहैया कराई। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसायटी दुनिया के सभी देशों में रेडक्रॉस आन्दोलन का प्रसार करने के साथ-साथ रेडक्रॉस के आधारभूत सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में भी कार्य कर रही है।

रेडक्रॉस की भूमिका शुरूआती दौर में युद्ध के दौरान बीमार और घायल सैनिकों, युद्ध करने वालों और युद्धबंदियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने तथा उन्हें उचित उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने तक ही सीमित थी किन्तु अब इस संस्था के दायित्वों का दायरा लगातार विस्तृत होता जा रहा है। दुनिया के किसी भी भाग में जब भूकम्प, बाढ़, भू-स्खलन या अन्य किसी भी प्रकार की प्राकृतिक अथवा मानवीय आपदा सामने आती है तो सबसे पहले ‘अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसायटी’ की टीमें वहां पहुंचकर राहत कार्यों में जुट जाती हैं। कहना गलत न होगा कि शांति और सौहार्द के प्रतीक के रूप में जानी जाने वाली इस संस्था ने अपने कर्मठ, समर्पित और कर्त्तव्यनिष्ठ स्वयंसेवकों के माध्यम से न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रेडक्रॉस फिलहाल 190 से भी ज्यादा देशों में सक्रिय है। विश्वभर में रेडक्रॉस के करीब 1.7 करोड़ स्वयंसेवक हैं। यही कारण है कि रेडक्रॉस दिवस को ‘अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस’ भी कहा जाता है। यह संस्था लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करती है और अपनी विभिन्न शाखाओं के जरिये में जगह-जगह रक्तदान शिविर लगाकर प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में रक्त एकत्रित करती है। वास्तव में रक्त इकट्ठा करने वाली यह विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी संस्था है, जिससे कैंसर, थैलेसीमिया, एनीमिया जैसी प्राणघातक बीमारियों से जूझ रहे हजारों लोगों की भी जान बचाई जाती हैं। रेडक्रॉस की पहल पर ही दुनिया का पहला ब्लड बैंक अमेरिका में 1937 में स्थापित हुआ था और वर्तमान में दुनियाभर के अधिकांश ब्लड बैंकों की देखरेख रेडक्रॉस तथा उसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा ही की जाती है। भारत में भी रक्त एकत्रित करने तथा वही रक्त जरूरतमंद लोगों के लिए सही समय पर उपलब्ध कराने का कार्य यह संस्था कई दशकों से लगातार कर रही है। भारत में ‘भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी अधिनियम’ के तहत वर्ष 1920 में रेडक्रॉस सोसायटी का गठन हुआ था और स्थापना के 9 वर्ष बाद इसकी सराहनीय गतिविधियों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसायटी ने ‘भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी’ को मान्यता प्रदान की थी। स्थापना के शुरूआती वर्षों में देश में रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते थे किन्तु वर्ष 1994 में रेडक्रॉस एक्ट में संशोधन करते हुए सोसायटी का पदेन अध्यक्ष महामहिम राष्ट्रपति को तथा सचिव केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बनाया गया। वर्तमान समय में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की देशभर में 750 से अधिक शाखाएं मानवता की सेवा में जुटी हैं। रेडक्रॉस सोसायटी के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वयं प्रेरित सेवा, एकता, सार्वभौमिकता इसके अहम उद्देश्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस की नजरों में दुनियाभर में सभी सोसायटियों की स्थिति, जिम्मेदारी तथा कर्त्तव्य एक समान हैं। यह एक ऐसा स्वैच्छिक राहत आन्दोलन है, जिसमें लाभ की इच्छा का कोई स्थान नहीं है। रेडक्रॉस का मुख्य उद्देश्य जीवन तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा करना एवं मानव मात्र का सम्मान सुनिश्चित करना है। यह राष्ट्रीयता, नस्ल, धार्मिक श्रद्धा, श्रेणी तथा राजनैतिक विचारधारा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती। रेडक्रॉस अपनी स्वायत्तता रखने के लिए स्वतंत्र है ताकि किसी भी परिस्थिति में यह आन्दोलन के सिद्धांतों के अनुरूप निर्बाध रूप से कार्य कर सके।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

... कि दिल अभी भरा नहीं

व्यंग्य

राजेंद्र बज

लेखक व्यंग्यकार हैं।

चतुर सुजान कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है, बहुत कुछ इसी तर्ज पर सत्ता के नियंता रहते सत्ता से पत्ता कट जाने पर भी जीते जी पद के प्रति आसक्ति भाव नहीं छूटता, तो इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि कमजोर दिल वाले जैसी भी परिस्थिति बने उसे भारी मन से ही सही लेकिन स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जिस किसी शख्सियत के रोम-रोम में जन सेवा का भाव विद्यमान हो जाता है, वह सत्ता के लिए छटपटाने लगती है। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता को ही जन सेवा का प्रमुख साधन माना जाता है। इसलिए किसी के पद से चिपकने को अन्यथा नहीं लेना चाहिए।

वैसे भी हर एक छोटे-बड़े पद के साथ छोटी-बड़ी जिम्मेदारियां भी अनिवार्य रूप से जुड़ी रहती है। यही कारण है कि राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न पदासीन शख्सियत को ‘जन सेवक’ का दर्जा दिया जाता है। यह निश्चित है कि जब जन-जन का सेवक स्वामी बनाकर कार्य करेगा, तो वह अधिक लगन एवं निष्ठा के साथ अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए थोड़ा बहुत कर्तव्यो को भी मूर्त रूप दे सकेगा। अन्यथा अधिकार ही नहीं होंगे तो, बिना अधिकार के कर्तव्य का पालन कैसे हो सकेगा ? अब यह तो सहज मानवीय स्वभाव है कि मन है कि मानता ही नहीं। ऐसे में किसी का जन सेवा से मन ही न भरे, ऐसी शख्सियत तो जनता को बड़े भाग्य से मिला करती है।

मैं सत्ता का और सत्ता मेरी, बस एक यही भाव जिसके चेतन और अवचेतन मन में गहरे रूप से समा जाता है, यकीन मानिए हमें उसको मोक्षपथगामी मान लेना चाहिए। क्योंकि जनसेवा और परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। इस अर्थ में सक्रिय राजनीति भी एक धर्म है। जिसे राजधर्म के रूप में सुशोभित किया जाता है। वास्तव में आजकल के दौर में आम आदमी गृहस्थ धर्म का परिपालन भी बमुश्किल कर पाता है, तो राजधर्म का पालन करना उसके लिए कहां संभव होगा? इसलिए तमाम छोटे बड़े राजनेताओं को हमें अगाध श्रद्धा के साथ अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। अन्यथा आजकल का जमाना तो ऐसा है कि किसको किसकी पड़ी है !

सत्ता के प्रति आसक्ति भाव की प्रबलता को सत्तालोलुपता करार देना उचित नहीं होगा। दरअसल सत्ता केवल देश और प्रदेश की ही नहीं होती। आदमी की हुकूमत यदि घर में चल रही है, तो यकीन मानिए, वही कोल्हू के बैल की तरह घर चला रहा होगा। जब ऐसी सत्ता का प्रभाव या कार्य क्षेत्र घर परिवार के दायरे से बाहर निकल कर दुनिया में प्रवेश करता है, तब इस सत्ता का स्वरूप अत्यंत व्यापक हो जाता है। जिसमें स्थानीय निकाय, प्रदेश व देश की सत्ता के साथ साथ अलग-अलग विभागों की सत्ता को शुमार किया जा सकता है। इसमें जो शख्सियत सत्ता की नियंता होती है, वही सबका साथ सबका विकास करते हुए जनकल्याण करती है।

हालांकि कभी-कभी आदमी एक बार सत्ता में आ जाता है तो एक अलग प्रकार की मदहोशी के आनंद से रूबरू होता है। अहम भाव कुछ इस कदर जागृत हो जाता है कि फिर अपने आगे किसी को कुछ न समझने का हाव भाव और व्यवहार दिखाई देने लगता है। इसमें दोष किसी का नहीं होता। दरअसल किरायेदार लंबे समय तक किरायेदार रहे, तो किराये पर ली गई संपत्ति पर मालिकाना बोध होने लगता है। एक अर्थ में यह लगाव है। इसे इस अर्थ में लेना चाहिए कि संबंधित शख्सियत आपकी हमारी सेवा चाकरी के लिए जबरदस्ती हमारे गले पड़ रही है। लेकिन उसकी इन भावनाओं को कौन समझेगा ?

ज्ञानी लोग कहा करते है कि हमारा शरीर किराये का है। इसको दाना पानी देते देते हम यह मान लिया करते हैं कि यह जो शरीर है, वह मेरा ही है। लेकिन ऊपर वाले का फरमान आते ही हमारी आत्मा को किराये का घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन इत्ती सी बात भी किसी के समझ में न आएं, तो क्या कहा जाएं !

दृष्टिकोण

चित्रा माली

सहायक प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता।

शिक्षा, विश्वविद्यालय और गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को लेकर अपने दृष्टिकोण को साकार रूप प्रदान करने के लिए 'ब्रह्मविद्यालय' की स्थापना की जो आगे चलकर शांतिनिकेतन, श्रीनिकेतन (ग्रामीण जनता में नई सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक प्रेरणा संचारित करने के उद्देश्य से तथा ग्रामीण शिल्प को उन्नत करने के उद्देश्य से इस संस्था को निर्मित किया गया था) और विश्व-भारती के रूप में साकार हुआ।

रवींद्रनाथ अपने बाल्य-जीवन में 'चारदीवारी में बंद दम घुटानेवाली' शिक्षा का कटु अनुभव प्राप्त कर चुके थे और उससे भाग खड़े हुए थे। इसलिए वह निरंतर क्लास रूम टीचिंग (दम घुटानेवाली शिक्षा) के विरुद्ध बोलते रहे और शांतिनिकेतन में उन्होंने अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रकृति के साहचर्य में रखने का प्रयास किया। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि गांव-गांव में फैला हुआ यह वृहत्तर मानवसमाज ही हमारी वास्तविक पुस्तक है। विद्यार्थियों को इसे ही पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए और जंगलों, पहाड़ों और मैदानों में फैली हुई विश्व-प्रकृति ही वास्तविक पाठशाला है। जबकि इसके विपरीत पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में पुस्तकों के माध्यम से ही मानवसमाज को समझने की समझ विकसित की जाती है। गुरुदेव कहते है कि शिक्षा कोई जड़ वस्तु नहीं है,वह चिन्मय वस्तु है। जो लोग पुस्तकों में बंद प्राणहीन शिक्षण प्रणालियों में आयोजित शिक्षा को ही प्रधान वस्तु समझते हैं,वे मूल में गलती करते हैं। सबसे बड़ी चीज है मनुष्यत्व। मनुष्य के संपर्क में आने से ही विद्यार्थी का सच्चा मनुष्यत्व जागृत होता है। प्राचीन भारत ने मनुष्य की इस महिमा को समझा था। इसीलिए उसने समस्त शिक्षा प्रणाली के केंद्र में गुरु को स्वीकार किया था। इसी अर्थ में भारतवर्ष की शिक्षा प्रणाली गुरुकुल प्रणाली है।

वर्ष 1912 में उन्होंने एक पत्र में लिखा था कि 'शिक्षा के संबंध में एक बहुत आवश्यक तथ्य सीखा था। हमने सीखा था कि आदमी आदमी से सीख सकता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जल से जलाशय होता है, दीपशिखा से शिखा जल उठती है और प्राण से प्राण संचारित होता है। मनुष्य को काट-छांट देने से मनुष्य नहीं रह जाता उस समय वह ऑफिस,अदालत या कल-कारखाने की सामग्री बन जाता है, उसी हालत में वह मनुष्य न बनकर 'मास्टर साहब' बनना चाहता है,इस हालत में वह ज्ञानदान के अयोग्य हो जाता है,सिर्फ पाठ-दान करने लगता है,सबक रटाने का उस्ताद हो जाता है'। शांतिनिकेतन विद्यालय की स्थापना के कुछ ही दिन बाद गुरुदेव ने अपने एक अध्यापक मित्र को पत्र लिखा था कि 'बालकों के अध्ययन का काल व्रत-पालन का काल है। मनुष्यत्व की प्राप्ति स्वार्थ नहीं, परमार्थ है,यह बात हमारे पितृ-पितामहों को मालूम थी। इस मनुष्यत्व की प्राप्ति की आधारभूत शिक्षा को वे ब्रह्मचर्य व्रत कहते थे। यह व्रत केवल पढ़ाई कर लेने और परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने का नाम नहीं है। संयम से,भक्ति-श्रद्धा से,शुचिता से और एकाग्रनिष्ठा से संसार के लिए और संसार से अतीत ब्रह्म के साथ अंनत योग-साधना के लिए प्रस्तुत होने की साधना को ही ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। यह एक धर्म व्रत है। दुनिया में बहुत-सी चीजें खरीद-बिक्री की सामग्री हैं, किंतु धर्म इससे भिन्न है। वह कुछ पण्य द्रव्य नहीं है। इसे एक ओर से मंगलेच्छा के साथ दान करना होता है और दूसरी ओर से विनीत भक्ति के साथ ग्रहण करना होता है। इसीलिए प्राचीन भारत की शिक्षा पण्य द्रव्य नहीं थी। आजकल जो लोग शिक्षा देते हैं वे शिक्षक हैं,लेकिन उन दिनों जो लोग शिक्षा देते थे वे गुरु होते थे। वे लोग शिक्षा के साथ एक ऐसी वस्तु देते थे जो गुरु और शिष्य के आध्यात्मिक संबंध से भिन्न किसी प्रकार का देना-पावन हो ही नहीं सकती। विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार के पारमार्थिक संबंध की स्थापना ही शांतिनिकेतन विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है'।

इस प्रकार शांतिनिकेतन विद्यालय की स्थापना के समय गुरुदेव रवींद्रनाथ टेगौर के मन में गुरु और शिष्य का आध्यात्मिक संबंध ही उद्देश्य था। आश्रम में विद्यालय की स्थापना करते समय कवि के चित्त में भी धर्म-भावना प्रबल थी इसीलिए उन्होंने शिक्षा को धर्म व्रत ही समझा था। उन्होंने अध्यापकों से आशा की थी कि वे लोग भी अध्यापन के पवित्र कार्य को व्रत के रूप में ही ग्रहण करें। अपने इसी पत्र में गुरुदेव आगे लिखते हैं कि 'मैं आशा किए बैठा हूं कि अध्यापकगण मेरे अनुशासन से नहीं बल्कि अपने भीतर के कल्याण-बीज को सहज ही विकसित करके आग्रहपूर्वक और आनंद के साथ इस ब्रह्मचर्य आश्रम के जीवन के साथ अपने जीवन को एक कर सकेंगे। कविवर के मन में उस समय 10 विद्यार्थियों को स्वदेश-भक्त बनाने की भी बड़ी प्रबल इच्छा थी। उन्होंने लिखा था, 'इस विद्यालय के छात्रों को मैं विशेष रूप से स्वदेश के प्रति भक्ति-श्रद्धावान बनाना चाहता हूं। जिस प्रकार माता-पिता में देवता का विशेष आविर्भाव होता है,उसी प्रकार अपने देश के प्रति भी देवता बुद्धि होनी चाहिए। पिता-माता जिस प्रकार देवता हैं उसी प्रकार स्वदेश भी देवता है। इसे लघुचित्त,अवज्ञा और घृणा यहां तक कि दूसरे देशों की तुलना में उसे छोटा समझना जैसे हल्के भाव से देखने की आदत विद्यार्थियों में जड़ न जमाने पाये,इस ओर मैं विशेष रूप से दृष्टि रखना चाहता हूं। अपनी स्वदेशी प्रकृति के विरुद्ध चलकर हम कभी सार्थकता नहीं प्राप्त कर सकेंगे'।

रवींद्रनाथ टेगौर ने विश्व-भारती और शांतिनिकेतन की अपनी परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए अत्यंत जटिल परिस्थितियों और तकलीफों को भी झेला। इस दौरान स्वजनों की मृत्यु, शिक्षकों और छात्रों की असमय मृत्यु के शोक को सहते हुए। स्वयं की स्वास्थ्यगत परेशानियों और आर्थिक तंगी के बावजूद शांतिनिकेतन का संचालन करना आसान नहीं था। शांतिनिकेतन के सुचारू संचालन के लिए उनकी पत्नी मृणालनी देवी ने भी अपने गहने बेच दिए थे। रवींद्रनाथ टेगौर ने देश-विदेश में घूम-घूम कर शांतिनिकेतन के लिए संसाधन

एकत्रित किए थे। यह संस्था के प्रति अपनी परिकल्पना के प्रति लगन और प्रतिबद्धता की अद्भुत मिसाल है। गुरुदेव की इसी प्रतिबद्धता ने कई महान व्यक्तियों को शांतिनिकेतन आने के लिए आकर्षित और प्रेरित किया। इनमें जगदानंद राय, क्षितिमोहन सेन,डब्ल्यू डब्ल्यू पियर्सन,विधुशेखर शास्त्री, लियोनार्ड एमहर्स्ट,तान युग शान,गुरुदयाल मल्लिक, दिनेन्द्रनाथ ठाकुर,हरिचरण बंधोपाध्याय, मौलाना जियाउद्दीन और बाद में हजारीप्रसाद द्विवेदी जी भी,ये सभी लोग गुरुदेव की इस परिकल्पना का हिस्सा बनते है और अपनी अमिट छाप शांतिनिकेतन पर छोड़ते हैं। इन्हीं शिक्षकों के सहयोग से गुरुदेव वर्ष 1923 में 'विश्वभारती' की स्थापना करते है। जिसमें उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के साथ पूर्णाग जीवन की भी व्यवस्था की गई थी।

कला-भवन, संगीत-भवन, विद्या-भवन (रिसर्च विभाग), शिक्षा विभाग,चीनी और तिब्बती विद्याओं के अध्ययन और शोध के लिए चीनी-भवन,हिंदी के उच्चतर अध्ययन और शोध के लिए हिंदी-भवन तथा देश-विदेश की धर्म-साधनाओं के अध्ययन के लिए दीनबंधु-भवन की स्थापना की गई। 'विश्वभारती' जीवंत शिशु की भांति उत्पन्न हुई है, कारखाने में ढली मशीन की भांति नहीं। रवींद्रनाथ टेगौर ने कहा था कि 'निर्जीव जीवन से भयंकर भार और कुछ नहीं है। इस बात का पूरा ध्यान रहे कि शांतिनिकेतन की शिक्षा निर्जीव न बनने पाए'। परंतु देश के चारों ओर का वातावरण जिस प्रकार की प्राणहीन शिक्षा के भार से बोझिल बना हुआ है, उसका प्रभाव बार-बार शांतिनिकेतन को अपने आदर्श के धरातल से नीचे आने को बाध्य करता रहा है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को इससे समझौता भी करना पड़ा था और इस उतार के लिए वे जीवन भर दुःखी और अशांत रहे। डिग्री का मोह,परीक्षा की गुलामी,विदेशी भाषा और भाव की नकल और रटंत विद्या का आग्रह,बढ़ती हुई नदी की बाढ़ के समान इन आदर्शों को दबोच लेने का प्रयत्न करते रहे और गुरुदेव उनसे जूझते रहे। वे निरंतर अपने लेखों,नाटकों, उपन्यासों, व्यंग्यों और व्याख्यानों से इस बीमार मनोवृत्ति को स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करते रहे। शांतिनिकेतन का हिंदी-भवन गुरुदेव द्वारा स्थापित संस्थाओं में से सबसे अंतिम है। हिंदी-भवन की स्थापना के समय गुरुदेव ने कहा था कि 'तुम्हारी भाषा परम शक्तिशाली है। बड़े-बड़े पदाधिकारी तुमसे कहेंगे कि हिंदी में कौन-सा रिसर्च होगा भला,तुम उनकी बातों में मत आना। मुझे भी लोगों ने बंग्ला में न लिखने का उपदेश दिया था। मैंने बहुत दुनिया देखी है। ऐसी भाषाएं भी हैं जो हमारी भाषाओं से कहीं कमजोर हैं परंतु उनके बोलनेवाले अंग्रेजी के विश्वविद्यालय नहीं चलाते। हमारे ही देश में लोग पर मुखापेक्षी हैं। तुम कभी अपना मन छोटा मत करना, कभी दूसरों की ओर मत ताकना। देखो मैं पके हुए बांस पर भरोसा नहीं करता। उन्हें झुकना कठिन है।

कच्चे बांस ही ले आओ। देशी भाषाओं को कच्चे युवकों की जरूरत है। साहस ज्यादा जरूरी है। लग पड़ोगे तो सब हो जाएगा। हिंदी के माध्यम से तुम्हें ऊंचे से ऊचें विचारों को प्रकट करने का प्रयत्न करना होगा। क्यों नहीं होगा? मैं कहता हूं जरूर होगा। ठूंठ-प्रवीणों से आशा नहीं है। नवीन युवा असाध्य-साधना कर सकते हैं'। हजारीप्रसाद द्विवेदी जी कहते है कि मुझे उनकी शब्दावली याद नहीं है,पर भाव यही है। ये मेरे चित्त पर वज्रलेख की तरह अंकित हो गए हैं। जिस दिन हिंदी-भवन का शिलान्यास किया गया था उस दिन दीनबंधु एंडड्रयूज अस्वस्थ थे। अस्वस्थता के चलते सोचा गया था कि उन्हें उत्सव स्थल पर नहीं ले जाया जाए,परंतु वे नहीं माने। वे बोले, 'देखो मैं जरूर चलूंगा और वैदिक मंत्र मैं ही पढ़ूंगा तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते हो'। उन्होंने ही शिलान्यास के अवसर पर इस शुभ अनुष्ठान का पौरोहित्य किया था। वे मनुष्य की शक्ति में पूर्ण विश्वास रखते थे। हिंदी को वे एक ऐसी लोकभाषा मानते थे जिसकी अद्भुत और अक्षय शक्ति अभी प्रकट नहीं हुई। वे कहते है तुम्हारी भाषा में बड़ी शक्ति है और बड़ी संभावनाएं हैं'। हिंदी-भवन का द्वारोदघाटन पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था। इस अवसर पर गुरुदेव भी उपस्थित थे। वे उस दिन बहुत प्रसन्न थे। हम लोगों के साथ देर तक बातें करते रहे और हम सबको हंसाते रहे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, सी.एफ.एंडड्र्यूज, जवाहरलाल नेहरू, मो.वि.हलवासिया, सीताराम सेकसरिया, भगीरथ कानोडिया, रामदेव चोखानी, बनारसीदास चतुर्वेदी इन सबका सहयोग हिंदी-भवन को कैसे मिल गया? क्या यह आकस्मिक घटना है? मेरा विश्वास है कि यह आकस्मिक बात नहीं है। हिंदी की यह अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति किसी महान भविष्य की ओर इंगित करती है। यह गुरुदेव का हिंदी के प्रति प्रेम और समूचे देश की संचार भाषा की स्वीकृति को भी दर्शाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शांतिनिकेतन के संस्मरण में लिखते हैं कि मैं 1930 नवंबर में शांतिनिकेतन प्रथम बार गया था और 1931 के वैशाख (8 मई) को गुरुदेव के 70वें जन्मदिन पर शामिल हुआ था। इस दिन बड़ी धूमधाम से गुरुदेव का जन्मदिन मनाया गया था। शांतिनिकेतन के आश्रमवासियों के लिए गुरुदेव का जन्मदिन विशेष उत्साह और उल्लास का दिन रहता था। उनके शिष्य उनको अपने बीच बिठाकर जन्मोत्सव मनाया करते थे। उस दिन गुरुदेव शुभ्र कौशेय वस्त्र की धोती, कुर्ता और उसी का सुंदर चादर उस देव-मनोहर शरीर पर यह वस्त्र इतने सुंदर लगते थे कि क्या बताऊँ! उनकी बड़ी-बड़ी प्रेमपूर्ण आंखों की जब याद आती है तो हूक-सी उठती है। गुरुदेव उत्सव के अनुरूप वेदमंत्रों के चुनाव में बहुत रस लेते थे। वे प्रत्येक मंत्र और गान को स्वयं देख लेते थे और आवश्यकता पड़ने पर मंत्रों के अनुवाद की भाषा का सुधार भी करते थे। प्रत्येक छोटे-से-छोटे काम को वे बहुत गंभीरतापूर्वक देखते थे। परंतु उस संपूर्ण गंभीरता में एक प्रकार का सहजभाव बना रहता था। यह सहज गंभीर-भाव उनकी अपनी विशेषता थी। इसी ने शांतिनिकेतन के प्रत्येक कार्य को इतना सुरुचिपूर्ण बना दिया है। आज भी गुरुदेव का जन्मदिन न केवल शांतिनिकेतन में अपितु बंगाल के भद्र जन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वेदमंत्रों का पाठ और रवींद्र गान इस उत्सव के अनिवार्य अंग है। आज भी भद्र जनों में गुरुदेव के शांतिनिकेतन को देखने का गुरुदेव के बारे में जानने का क्रेज बरकरार है जो उन्हें जोड़ासांको और शांति निकेतन तक ले जाता है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को शत-शत नमन।

वक्रोक्ति

रिंकल शर्मा

लेखक कहानीकार हैं।

सदियों तक जिज्जी कहलाएगी 'महान साहित्यकार'

दुर्भाग्य से, जिज्जी बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थीं। इसकी जानकारी उनके अलावा किसी और को नहीं थी। वे घर की मँझली औलाद थीं, इसलिए माता-पिता ने अतिरिक्त लाड़-प्यार देकर उन्हें बिगाड़ने की भूल नहीं की। जिज्जी शुरू से ही बेहद शांतिप्रिय थीं, उनकी कभी किसी से कहासुनी नहीं हुई, क्योंकि वे सीधे हाथापाई में विश्वास रखती थीं, इससे मामला जल्दी निपट जाता था। पर्यावरण प्रेमी थीं सो अन्न की बरबादी भी बिलकुल पसंद नहीं थी, इसीलिए कभी-भी नाश्ते के चक्कर में नहीं पड़ीं, हमेशा दोपहर खाने से पहले ही सोकर उठतीं थीं। देर तक सोने से ही जिज्जी बड़े-बड़े सपने देख पायीं। पर देखते-देखते उनके सपने इतने बड़े हो गए कि उनके सामने उनकी पढ़ाई बहुत छोटी रह गयी। दसवीं से ऊपर कभी छू भी नहीं पायी। उनके अंक हमेशा पेंतालीस प्रतिशत पर स्थिर रहे, न कभी इससे ज़्यादा, न कभी कम। यदि किसी राजनैतिक पार्टी के पास इतने स्थिर वोट होते, तो किसी भी गठबंधन की सरकार में उनका स्थान हमेशा सुरक्षित रहता। लेकिन उन्होने इस बात पर कभी अहंकार नहीं किया। अपनी इस स्थिरता के लिए उन्होने हमेशा भगवान का धन्यवाद किया क्यूंकी इतनी स्थिरता तो शेयर मार्केट में बड़े-बड़े निवेशकों को भी नसीब नहीं होती।

बचपन से ही जिज्जी बड़े ऊँचे ख्यालात की थीं। ये डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बनने का ख़याल उन्होने कभी नई पाला क्योंकि ये सब तो आम लोग करते हैं, उनका सोचना था कि जब भगवान ने उन्हें औसत से थोड़ा नीचे रखा है, तो ज़रूर उनका जन्म कुछ असाधारण करने के लिए हुआ है। हाँ, उनके घरवाले उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। उन्हें लगता था कि जिज्जी 'कुछ' नहीं करेंगी। जिज्जी को लगता था कि वो 'कुछ बड़ा' करेंगी। अब यह 'कुछ बड़ा' क्या होगा यह उन्हें 'कुछ' नहीं पता था। लेकिन इस 'कुछ' से परिवार में वैचारिक संतुलन बना हुआ था।

दरअसल जिज्जी को तो कुछ ऐसा करना था जहाँ बिना काम के भी काम माना जाए और जिज्जी महान कहलाएँ। आखिरकार थोड़े बहुत सोच-विचार के बाद उन्होने कवयित्री बनने का निर्णय लिया। इस निर्णय के पीछे उनके ठोस, तर्कसंगत और पूरी तरह स्वार्थ-रहित कुछ ख़ास कारण थे। पहला - अँग्रेजी में उनका हाथ तंग था। अंग्रेज़ी में जिज्जी उतनी ही निपुण थीं जितना आम आदमी सरकारी नीतियों को समझने में। सौभाग्य से हिन्दी साहित्य इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहाँ अंग्रेज़ी को कोसना स्वीकार्य भी है और अनिवार्य भी। दूसरा साहित्य में रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं होती। जीवनभर आपकी कवितायें भले अधपकी रह जाएँ लेकिन बाल पकते-पकते आपको अध्यक्ष पद पर प्रमोशन मिल ही जाता है। तीसरा - ग्लेमर के मामले में साहित्य मरुस्थल जैसा है, जहां मृगतृष्णा भी ठंडक देती है। कवयित्री के पास कवित्त ज्ञान ज़्यादा न हो पर सौंदर्य और आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, जोकि उनके पास थोक में था।

आखिरी सबसे बड़ा कारण था कि उन्हें जीवन में सीधे 'महान' बनना था वो भी बिना मेहनत, शॉर्टकट से। और साहित्य की दुनिया ऐसी है जहां शुरुआत में भले ही लोग आपको हल्के में लें, लेकिन समय के साथ वही लोग आपको 'वरिष्ठ', 'प्रख्यात' और 'महान' जैसे शब्दों से अलंकृत कर देते हैं। बस आप लेखन की निरंतरता बनाए रखें और अपनी कविताओं की भाषा को न्यायालय की भाषा की तरह जटिल रखें। ताकि आपकी कविता को समझना तो दूर उसके विरुद्ध, कुछ कहना भी अपराध माना जाए। फिर आप देखेंगे, कुछ समय बाद, लोग आपकी रचनाओं में ऐसे-ऐसे गूढ़ अर्थ ढूँढने लगेंगे जो आपने कभी खुद भी नहीं सोचे होंगे। बस इन्हीं कुछ सहूलियतों के आधार पर जिज्जी ने जोड़-तोड़ की कविताएँ लिखना शुरू किया।

अक्सर विद्वानों को कहते सुना है कि कला का अर्थ 'आत्मा का आनंद' होता है। हालाँकि यह सुनकर आत्मा पर तरस आता है क्यूंकि अक्सर कलाकारों को पेट की संतुष्टि के लिए जुगत लगाते देखा है। पर हमारी जिज्जी के लिए कला का अर्थ निकला- कल-आ, कल-आ। क्योंकि जब भी जिज्जी किसी भोले-भाले श्रोता को पकड़कर, उसे अपनी कविता सुनाने की कोशिश करतीं, उसके चेहरे पर अचानक राष्ट्रिय संकट उमड़ आता। वह कभी घड़ी देखता, कभी मोबाइल टटोलता, अपनी इतनी व्यस्तता दिखाता जैसे देश की अर्थव्यवस्था उसी के भरोसे चल रही हो। फिर बनावटी, शिष्ट मुस्कान से कह देता- 'वाह! बहुत बढ़िया... कल आना, आराम से सुनूंगा।'

लोगों ने उन्हें सुनने के बजाय टालना शुरू किया पर जिज्जी ने इसे प्रोत्साहन समझकर, कवि-सम्मेलनों की ओर रूख किया। बस यहीं से उनका असली साहित्यिक सफ़र शुरू हुआ।

लेकिन इस सफ़र में जिज्जी के सामने नई समस्या थी कि मंचों के लायक 'ठोस' कविता लिखी कैसे जाए? उन्होने थोड़ा सोचा, फिर तुरंत सोचना बंद कर दिया क्योंकि सोचने में मेहनत लगती है। फिर समस्या का सरल समाधान निकाला कि- खुद क्यों लिखें? जब दुनिया में पहले से इतनी कविताएँ मौजूद हैं, तो नई लिखकर साहित्य पर अतिरिक्त बोझ क्यों डाला जाए? फिर साहित्य में तो वैसे भी ईमानदारी दुर्लभ है। इसीलिए उन्होने 'सृजनात्मक उधारवाद' को अपनाया। उनका मानना था कि 'मौलिकता' सिर्फ़ एक भ्रम है और भ्रम से जितना दूर रहा जाए, उतना अच्छा। फिर, कवि सम्मेलनों पर अध्ययन के बाद उन्हें यह पता चल चुका था कि आधे से ज़्यादा कवि-कवयित्रियाँ इसी बिरादरी के हैं। यह एक ऐसा विस्तृत परिवार है, जहाँ लोग, एक-दूसरे की रचनाओं से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्हें अपना बना लेते हैं। फ़र्क बस इतना है कि आम भाषा में जिसे 'चोरी' कहते हैं, परिवार के लोग इसे 'प्रेरणा' कहते हैं। मगर जिज्जी ने इसे 'साहित्यिक रिसाइकलिंग' का नाम दिया। वर्तमान में तो पर्यावरण की रक्षा के लिए रिसाइकलिंग बहुत आवश्यक है फिर चाहे कचरा हो या कविता।

साहित्यिक रिसाइकलिंग की कला सीखने में बारीकियों पर उन्होने ख़ास ध्यान दिया जैसे- किस रस की, कौन सी कविता, कहाँ से उठानी है, कितने शब्द बदलने हैं, कहाँ अल्पविराम लगाना है और कहाँ भावनात्मक विराम देना है इत्यादि। धीरे-धीरे कुशलता के साथ शब्दों की अदला-बदली से ऐसी कविता लिखने लगीं कि मूल लेखक भी अपनी कविता पहचान न पाये। जिज्जी ने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना।

धीरे-धीरे उन्होने मंचों पर धावा बोलना शुरू किया और चिल्ला-चिल्लाकर ओज की कवितायें पढ़नी शुरू कर दीं। सौन्दर्य के मुख से, आत्मविश्वास से भरी, अदाओं में लिपटी ओज की कवितायें, जब लोग सुनते, तो समझ भले न आयीं हों, पर तालियाँ खूब ज़ोर से बजाते। और यही उनकी असली सफलता थी, क्योंकि समझने लगते, तो खतरा बढ़ जाता। हाँ, कभी, कहीं, कोई व्यक्ति बुद्धिजीवी बनकर पूछ बैठता है कि 'आपकी कविता का मूल भाव क्या है?' तो जिज्जी तुरंत यह कहकर चुप करा देतीं कि 'कविता को समझना नहीं, महसूस करना चाहिए।' क्यूंकि जिज्जी समझ जाती थीं कि यह बुद्धिजीवी नहीं है, यदि होता तो कविता सुनने क्यूँ आता?

समय के साथ उन्होने मंचीय रणनीति भी सीख ली। जिज्जी मंच पर पहुँचते ही आयोजक की खूब प्रशंसा करतीं ताकि अगली बार का बुलावा पक्का हो जाए। फिर, मंच पर विराजमान अध्यक्ष को गुरु बताकर, अपनी कविता को उसके गले की हड्डी बना देतीं। अब, अध्यक्ष के पास उनकी प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। जब अध्यक्ष तारीफ़ों का फ्लाईओवर बना दे, तो आलोचक और समीक्षक वैसे ही चुप हो जाते हैं जैसे मीटिंग में बॉस के बोलने के बाद, कर्मचारी।

तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बतौर कवयित्री जिज्जी पारंगत हो चुकी हैं। और अब उन्होने साहित्य की दूसरी विधाओं में भी दखल देना शुरू कर दिया है ताकि कोई भी मंच अछूता न रहे। साथ ही बड़े-बड़े पुरस्कार देने वाले संस्थानों में घुसपैठ भी शुरू कर दी है। जैसे ही दो-चार पुरस्कार उनकी झोली में गिरेंगे, 'प्रख्यात' और 'प्रतिष्ठित' शब्द स्वतः उनके नाम के साथ जुड़ जाएंगे। फिर दिन वह दूर नहीं जब जिज्जी की कविताएँ पाठ्यक्रम में लगाई जाएँगी, उन पर शोध होंगे, स्कूलों में उनकी जीवनी पढ़ाई जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी 'साहित्यिक रिसाइकलिंग' की परंपरा को आगे बढ़ा सकें। और सदियों तक जिज्जी 'महान साहित्यकार' के रूप में जानी जाएँगी।

अभिव्यक्ति

डॉ. शैलेश शुक्ला

लेखक पत्रकार हैं।

क्या न्यायालयों को आलोचना से भयभीत होना चाहिए?

भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक और नागरिक अधिकारों का अंतिम प्रहरी माना जाता है। संसद कानून बना सकती है, सरकार प्रशासन चला सकती है, किंतु संविधान की आत्मा की रक्षा का अंतिम दायित्व न्यायपालिका पर ही है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को लोकतंत्र का नैतिक स्तंभ कहा जाता है। किंतु किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की वास्तविक शक्ति उसकी आलोचना से बच निकलने में नहीं, बल्कि आलोचना को सुनने और उससे स्वयं को बेहतर बनाने की क्षमता में निहित होती है। आज भारत में यह प्रश्न अत्यंत गंभीरता से उठ रहा है कि क्या न्यायपालिका को आलोचना से ऊपर माना जा सकता है, अथवा उसे भी लोकतांत्रिक विमर्श के अंतर्गत जवाबदेही और पारदर्शिता के मानकों पर परखा जाना चाहिए।

यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायपालिका केवल कानूनी संस्था नहीं, बल्कि सार्वजनिक विश्वास पर आधारित नैतिक संस्था भी है। न्यायालयों के पास न सेना है, न पुलिस बल; उनकी वास्तविक शक्ति जनता के विश्वास में निहित होती है। यदि जनता को यह लगने लगे कि न्यायपालिका आलोचना से डरती है या अपने विरुद्ध उठने वाली हर आवाज़ को 'अवमानना' कहकर दबाना चाहती है, तो धीरे-धीरे उसका नैतिक अधिकार कमजोर पड़ सकता है। लोकतंत्र में कोई भी संस्था इतनी पवित्र नहीं हो सकती कि वह जनचर्चा और आलोचना से परे हो जाए।

भारत में न्यायालय की अवमानना का कानून औपनिवेशिक मानसिकता की देन माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 भी इस शक्ति को परिभाषित करता है। दृष्टि आईएएस के एक विश्लेषण में बताया गया है कि भारतीय कानून के अनुसार अवमानना दो प्रकार की होती है–सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। आपराधिक अवमानना में न्यायालय की 'गरिमा को ठेस पहुँचाने' या न्यायपालिका को 'स्कैंडलाइज़' करने जैसे व्यापक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यही वह क्षेत्र है जहाँ लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और न्यायिक संवेदनशीलता के बीच टकराव पैदा होता है।

समस्या यह है कि 'न्यायपालिका की आलोचना' और 'न्यायपालिका का अपमान' हमेशा एक ही बात नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति किसी निर्णय की तार्किक आलोचना करता है, न्यायिक पारदर्शिता पर प्रश्न उठाता है, या न्यायिक नियुक्तियों में सुधार की मांग करता है, तो उसे लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। किंतु भारत में कई बार ऐसा प्रतीत हुआ है कि न्यायपालिका आलोचनात्मक टिप्पणियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। वर्ष 2020 में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही ने इसी बहस को राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्जीवित कर दिया था। अनेक विधि विशेषज्ञों, पूर्व न्यायाधीशों और बुद्धिजीवियों ने तब यह तर्क दिया था कि न्यायपालिका की गरिमा आलोचना को दंडित करने में नहीं, बल्कि आलोचना का उत्तर अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता से देने में निहित है।

वास्तविकता यह है कि भारतीय न्यायपालिका के भीतर समय-समय पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप सामने आते रहे हैं। 1990 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी. रामास्वामी पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे और संसद में उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि राजनीतिक कारणों से वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, किंतु इस घटना ने यह मिथक तोड़ दिया कि न्यायपालिका पूर्णतः त्रुटिहीन संस्था है। इसके बाद भी अनेक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर संपत्ति, प्रभाव और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगते रहे हैं।

कई मामलों में मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि कुछ न्यायाधीशों के पास उनकी घोषित आय से कहीं अधिक मूल्य की संपत्तियाँ पाई गईं। कुछ मामलों में आयकर छापों और जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने भी संदेह को बढ़ाया। हाल के वर्षों में न्यायपालिका से जुड़े कुछ विवादों में 'सैकड़ों करोड़ की संपत्ति' जैसे शब्द सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बने। यद्यपि किसी भी आरोप की अंतिम सत्यता केवल न्यायिक जांच से ही सिद्ध हो सकती है, फिर भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे आरोप सामने आते हैं तो क्या समाज को उन पर चर्चा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार के संभावित मामलों पर प्रश्न उठाना भी अवमानना माना जाएगा? लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि सार्वजनिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति आलोचना से ऊपर नहीं हो सकता। न्यायाधीश भी अंततः सार्वजनिक जीवन का हिस्सा हैं और उनके निर्णय करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि वह न्यायिक प्रक्रियाओं, नियुक्तियों और आचरण पर प्रश्न उठा सके। यह आलोचना तथ्याधारित और जिम्मेदार होनी चाहिए, किंतु उसका दमन लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कई लोकतांत्रिक देशों ने न्यायपालिका के प्रति अधिक उदार और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है। अमेरिका में न्यायालय की अवमानना का दायरा भारत की तुलना में कहीं अधिक सीमित है। वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यंत व्यापक रूप से संरक्षित किया गया है। अमेरिकी न्यायपालिका के विरुद्ध तीखी सार्वजनिक आलोचनाएँ सामान्य बात मानी जाती हैं। अमेरिकी मीडिया और विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की कठोर समीक्षा होती है, किंतु केवल आलोचना के आधार पर अवमानना की कार्रवाई बहुत दुर्लभ है। दृष्टि आईएएस के एक तुलनात्मक अध्ययन में बताया गया है कि अमेरिका में अवमानना का उपयोग मुख्यतः न्यायिक आदेशों के उल्लंघन या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा के मामलों तक सीमित है।

ब्रिटेन, जहाँ से भारत ने अवमानना कानून की विरासत प्राप्त की, वहाँ भी पिछले दशकों में इस कानून का दायरा काफी सीमित कर दिया गया है। 2013 में ब्रिटेन ने 'स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट' जैसी अवधारणा को लगभग अप्रासंगिक बना दिया। यह स्वीकार किया गया कि लोकतांत्रिक समाज में न्यायालयों की आलोचना को अपराध नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि वह सीधे न्यायिक प्रक्रिया को बाधित न करे। ब्रिटिश विधि आयोग ने भी यह माना कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा आलोचना को दबाने से नहीं, बल्कि अपने कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता से बनती है।

कनाडा में न्यायपालिका पर आलोचना को लोकतांत्रिक विमर्श का स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है। वहाँ न्यायिक परिषदें न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करती हैं। यदि किसी न्यायाधीश पर नैतिक या वित्तीय अनियमितता का आरोप हो, तो उसकी स्वतंत्र जांच की व्यवस्था है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में भी न्यायपालिका के विरुद्ध सार्वजनिक आलोचना को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, बशर्ते वह न्यायिक प्रक्रिया में बाधा न उत्पन्न करे।

यूरोपीय देशों में पारदर्शिता की संस्कृति और भी अधिक विकसित है। जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों में न्यायपालिका की प्रशासनिक प्रक्रियाएँ काफी खुली होती हैं। कई देशों में न्यायाधीशों की संपत्ति घोषणाएँ सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। वहाँ यह समझ विकसित हो चुकी है कि पारदर्शिता न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे और अधिक वैधता प्रदान करती है।

भारत में समस्या यह है कि न्यायपालिका स्वयं अपनी जवाबदेही तय करती हुई दिखाई देती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाला कॉलेजियम सिस्टम लंबे समय से विवादों में है। आलोचकों का कहना है कि इसमें पारदर्शिता का अभाव है और 'जज ही जजों की नियुक्ति कर रहे हैं' जैसी स्थिति लोकतांत्रिक दृष्टि से आदर्श नहीं मानी जा सकती। कई बार नियुक्तियों और स्थानांतरणों के पीछे के कारण सार्वजनिक नहीं किए जाते, जिससे संदेह और अविश्वास बढ़ता है।

इसी प्रकार न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए भी कोई पूर्णतः स्वतंत्र और प्रभावी तंत्र नहीं है। यदि किसी मंत्री, सांसद या नौकरशाह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो उसके विरुद्ध जांच एजेंसियाँ सक्रिय हो जाती हैं। किंतु न्यायपालिका के मामले में प्रक्रिया अत्यंत जटिल और सीमित है। इससे जनता में यह धारणा बनती है कि न्यायपालिका स्वयं को जवाबदेही से ऊपर मानती है।

हालांकि यह भी सत्य है कि भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर आत्मसुधार के प्रयास किए हैं। कुछ न्यायाधीशों ने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक किया। न्यायालयों की कार्यवाही का डिजिटलीकरण हुआ। कुछ महत्वपूर्ण मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई। कॉलेजियम के निर्णयों का आंशिक प्रकाशन भी शुरू हुआ। ये कदम सकारात्मक हैं, किंतु अभी भी पर्याप्त नहीं कहे जा सकते।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आलोचना वास्तव में न्यायपालिका को कमजोर करती है? इतिहास बताता है कि किसी भी संस्था की विश्वसनीयता पारदर्शिता से बढ़ती है, दमन से नहीं। मीडिया, नागरिक समाज और विधि विशेषज्ञ यदि न्यायिक प्रक्रियाओं पर प्रश्न उठाते हैं, तो यह लोकतंत्र की जीवंतता का संकेत है। यदि न्यायपालिका आलोचना को स्वीकार कर उससे सीखती है, तो उसका नैतिक अधिकार और अधिक मजबूत होगा।

यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि आलोचना और अराजकता में अंतर होता है। निराधार आरोप, व्यक्तिगत चरित्रहनन और दुर्भावनापूर्ण अभियान निश्चित रूप से अनुचित हैं। न्यायपालिका को ऐसे मामलों में स्वयं की रक्षा का अधिकार है। किंतु तथ्याधारित, तार्किक और सार्वजनिक हित में की गई आलोचना को दंडित करना लोकतांत्रिक समाज के लिए खतरनाक प्रवृत्ति बन सकता है।

आज सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के युग में सूचनाओं का प्रवाह अत्यंत तीव्र हो चुका है। अब संस्थाएँ बंद कमरों में रहकर अपनी विश्वसनीयता नहीं बचा सकतीं। जनता अधिक जागरूक है और जवाबदेही की मांग पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। ऐसे समय में न्यायपालिका को भी यह स्वीकार करना होगा कि लोकतांत्रिक सम्मान आदेश से नहीं, बल्कि विश्वास से प्राप्त होता है।

यदि न्यायपालिका वास्तव में अपनी गरिमा को सुदृढ़ करना चाहती है, तो उसे आलोचना से भयभीत होने के बजाय पारदर्शिता की दिशा में और साहसिक कदम उठाने होंगे। न्यायाधीशों की संपत्ति का अनिवार्य सार्वजनिक विवरण, न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता, शिकायतों की स्वतंत्र जांच, और अवमानना कानून की पुनर्समीक्षा जैसे कदम समय की मांग हैं।

भारतीय लोकतंत्र का भविष्य केवल स्वतंत्र न्यायपालिका पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ऐसी न्यायपालिका पर निर्भर करता है जो स्वतंत्र होने के साथ-साथ उत्तरदायी भी हो। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा आलोचना को दबाने से नहीं, बल्कि यह दिखाने से बनेगी कि वह स्वयं को भी संविधान और लोकतंत्र के मानकों के अधीन मानती है।

अंततः, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आलोचना लोकतंत्र की शत्रु नहीं, बल्कि उसकी जीवनरेखा है। न्यायपालिका यदि इस सत्य को स्वीकार कर लेती है, तो वह केवल एक शक्तिशाली संस्था ही नहीं, बल्कि वास्तव में एक महान लोकतांत्रिक संस्था बन सकती है। और शायद यही वह क्षण होगा जब जनता न्यायपालिका को केवल भय या औपचारिक सम्मान से नहीं, बल्कि वास्तविक विश्वास और नैतिक श्रद्धा से देखेगी।

विश्व कवि गुरूदेव ने कहा था- 'कला, ज्ञान की प्रयोगशाला है'

भोपाल। जीवन आनंद का उत्सव है और कलाओं में इसकी सुन्दर छवियों को देखा जा सकता है। गुरूदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर का जीवन और सृजन यही संदेश देता प्रेम, प्रकृति और करूणा की पुकार बन गया। विश्व मानवता उनके लिए सबसे बड़ा मूल्य था। वे संस्कृति की घनी छाँव थे। उन्होंने कहा था- कला, ज्ञान की प्रयोगशाला है।

टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केन्द्र के परिसर में इस भावभीने उद्गार के बीच गुरूदेव टैगोर को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। आरएनटीयू के मुक्तधारा सभागार में टैगोर जयंती का 'प्रणति पर्व' था। कुलगुरू डॉ. आर.पी. दुबे, निदेशक एजीयू डॉ. अदिति चतुर्वेदी वत्स, कुलसचिव डॉ. संगीता जौहरी, टैगोर कला केन्द्र के निदेशक विनय उपाध्याय तथा टैगोर नाट्य विद्यालय के निदेशक अविजीत सोलंकी ने इस अवसर पर संबोधित किया। वक्ताओं ने शिक्षा और कला में गुरूदेव के रचनात्मक प्रयोगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि रबीन्द्र बाबू जीवन को समग्रता में देखने के हिमायती थे। साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, दर्शन,

अध्यात्म और विज्ञान में उनकी गहरी रूचि थी। वे संस्कृति की घनी छाँव की तरह याद आते हैं। टैगोर की मूर्ति पर सामूहिक पुष्पांजलि और उनके द्वारा रचित राष्ट्रगान से समारोह का मंगलाचरण हुआ।

विनय उपाध्याय ने समारोह की प्रस्तावना रखते हुए अपने संबोधन में टैगोर के रचनात्मक कौशल और 'विश्व रंग' के माध्यम से उनके विश्वव्यापी सांस्कृतिक विस्तार को रेखांकित किया। विनय ने कहा कि टैगोर कला केन्द्र द्वारा स्थापित पुस्तकालय और संदर्भ केन्द्र की बहुमूल्य सौगात टैगोर की विरासत को जानने-समझने की नई दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यक्रम के पूर्वरंग में नाट्य विद्यालय के छात्रों आशुतोष, लवकुश कुमार, आर्यन, विक्रम, दक्ष कौशिक, विजय सरदार, दुर्गेश कुमार तथा मिहिर कसेरा ने गुरूदेव की कविताओं का भावपूर्ण पाठ किया। यह चयन 'रंग संवाद' के सहायक संपादक मुदित श्रीवास्तव ने किया। प्रेम, प्रकृति और मानवीय संबंधों की सुगंध से सराकोर इन रचनाओं को सुनना श्रोताओं के लिए रोचक अनुभव था। आरंभ में टैगोर के गीतों पर केन्द्रित संगीत-नृत्य रूपक 'गीतांजलि' पुस्तिका का लोकार्पण किया गया। टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तथा विश्व रंग फाउण्डेशन के साझा संयोजन में परिकल्पित इस आत्मीय प्रसंग में मानविकी तथा उदार कला संकाय की डीन डॉ. रूचि मिश्रा तिवारी, विश्व रंग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकास अवस्थी, भारतीय ज्ञान परंपरा केन्द्र की संयोजक डॉ. सावित्री सिंह परिहार सहित विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी तथा छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे।

मप्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य मंगल सिंह धुर्वे 8 मई को बैतूल प्रवास पर

बैतूल। मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य मंगल सिंह धुर्वे 8 मई को बैतूल प्रवास पर रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजातीय आयोग के सदस्य श्री धुर्वे प्रातः 9 बजे बैतूल से चिखली नांदा होते हुए भीमपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मोहदा के बर्राढाना के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रातः 10.30 बजे भीमपुर विकासखंड के बर्राढाना में पीड़ित परिवारों से राहत वितरण के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके बाद दोपहर 12.30 बजे भीमपुर, चिचोली, मलाजपुर होते हुए ग्राम पंचायत नीमपानी के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री धुर्वे 4 बजे ग्राम पंचायत नीमपानी में लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद 5 बजे शाहपुर होते हुए ग्राम कछार के लिए प्रस्थान करेंगे। यहां साय 6 बजे भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री धुर्वे का रात्रि 7.30 बजे कछार से ग्रह ग्राम रामपुर रैयत आगमन एवं रात्रि विश्राम है।

मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना कार्य में नागरिक सही जानकारी दें

बैतूल। जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य जिले में किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के तहत प्रगणक घर-घर पहुंचकर मोबाइल द्वारा एचएलओ ऐप में जानकारी संकलित कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों से जनगणना कार्य में सहयोग प्रदान करने एवं सही एवं प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की गई है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने कहा है कि जनगणना से प्राप्त आंकड़े शासन की विभिन्न विकास योजनाओं, आधारभूत सुविधाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह प्रगणकों को तथ्यात्मक एवं स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराए। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि जनगणना के दौरान किसी भी प्रकार का दस्तावेज, बैंक संबंधी जानकारी, आधार नंबर, पैन नंबर अथवा ओटीपी नहीं मांगा जाता है। प्रगणक केवल नागरिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर विवरण दर्ज करते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि प्रगणक के घर पहुंचने पर उनका पहचान पत्र अवश्य देखें तथा जनगणना कार्य में सकारात्मक सहयोग प्रदान करें। साथ ही यदि किसी नागरिक द्वारा स्व-गणना की गई है, तो संबंधित एसई-आईडी प्रगणक को उपलब्ध कराएं। प्रशासन ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी अथवा अफवाहों पर ध्यान न दें। मकान सूचीकरण दौरान ली गई जानकारी पूर्णतः गोपनीय है एवं यह जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त नहीं की जा सकती है।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि 2024-25 में लक्ष्य प्राप्ति पर बैतूल कलेक्टर सम्मानित

बैतूल। सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य राशि 7,61,100 से अधिक 7,80,309 एकत्रित करने पर कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे को राज्यपाल म.प्र. मंगुभाई पटेल द्वारा ट्रॉफी एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें औपचारिक रूप से कैप्टन (आईएन) सुमीत सिंह (से.नि.), जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा दिया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर वंदना जाट भी मौजूद रहीं, जिनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप यह लक्ष्य प्राप्त हो सका। परिवहन अधिकारी बैतूल अनुराग शुक्ला के कार्यालय द्वारा एक लाख रुपये से अधिक की राशि दान की गई।

गौरतलब है कि बैतूल जिले ने लगातार दो वर्षों से यह लक्ष्य हासिल कर सम्मान प्राप्त किया है। इससे पहले वर्ष 2021-22 में भी यह सम्मान जिले को मिला था। आशा है कि इस वर्ष भी दिए गए लक्ष्य को प्राप्त कर बैतूल जिला पुनः यह गौरव हासिल करेगा। इस राशि का उपयोग संचालनालय, सैनिक कल्याण म.प्र. भोपाल के मार्गदर्शन में शहीद सैनिकों, उनके आश्रितों, परिजनों, विकलांग सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सैनिक 35-40 वर्ष की कम आयु में ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उस समय उनके बच्चे छोटे और माता-पिता वृद्ध होते हैं। घर की

जिम्मेदारियों व बच्चों की शिक्षा के लिए प्राप्त पेंशन पर्याप्त नहीं होती। इसलिए इस निधि का सर्वाधिक उपयोग पूर्व सैनिकों के आश्रितों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने में किया जाता है। झण्डा दिवस निधि में नागरिकों का स्वैच्छिक अनुदान एक गरिमामयी परंपरा है। यह शहीदों के परिवारों, जरूरतमंद विकलांग पूर्व सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के प्रति आभार प्रकट करने का उत्तम माध्यम है। राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष से यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी विभाग, संस्था या व्यक्ति द्वारा एक लाख रुपये या अधिक राशि दान करने पर उन्हें माननीय राज्यपाल द्वारा लोकभवन में आयोजित सम्मेलन में प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा । इसी क्रम में इस वर्ष माननीय राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने दिनांक 21 अप्रैल 2026 को लोकभवन में 25 दानदाताओं को हर्षोल्लास के साथ सम्मानित किया।

नपा उपाध्यक्ष का मोबाइल चोरी

बैतूल। नगरपालिका उपाध्यक्ष महेश राठौर का वीवो कंपनी का मोबाइल पिछले दिनों सदर बाजार में चोरी हो गया। चौकाने वाली बात यह है कि ढाई वर्ष में सदर बाजार में ही उनका तीसरा मोबाइल चोरी हुआ है। सदर बाजार की व्यवस्था पर खुद नपा उपाध्यक्ष राठौर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे अंबेडकर वार्ड में निवास करते हैं और सदर बाजार में रविवार या गुरुवार को सब्जी खरीदने जाते हैं। बीते रविवार भी उन्होंने वीवो कंपनी का मोबाइल ऊपर की जेब में रखा था। इसी दौरान अज्ञात चोर ने मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि 25 हजार कीमत यह मोबाइल एक वर्ष पहले ही खरीदा था। इसके पहले भी दो बार सदर बाजार से ही मोबाइल चोरी हो चुका है। नपा उपाध्यक्ष ने पुलिस से सदर बाजार के दिन नियमिति रूप से निगरानी करने के लिए आग्रह किया है। वे इस संबंध में जल्द ही एसपी वीरेंद्र जैन से भी मुलाकात करने वाले हैं।

जनसहभागिता से जल संरक्षण व संवर्धन के क्षेत्र में बैतूल को मॉडल बनाएं : कलेक्टर

बैतूल। पंख कार्यक्रम अंतर्गत दृष्टि योजना के तहत कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने सभी स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त करते कहा कि जिले में पर्यावरण संरक्षण, वन ऊर्जा, नशा मुक्ति, प्राकृतिक कृषि सहित विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में संस्थाओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन में भी इन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करते कहा कि अभी भी जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने पूर्व में किए गए जल संरक्षण कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे आगामी परियोजनाओं के लिए उपयोगी मार्गदर्शन मिलेगा। उन्होंने सभी संस्थाओं से बैतूल जिले को जल संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में मॉडल जिला बनाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि बैतूल जिले के नागरिक सामाजिक

जिम्मेदारियों के प्रति सजग एवं सक्रिय हैं। आगामी जल संरक्षण, कृषि एवं विकास परियोजनाओं में अपने सुझाव एवं सहयोग देकर जिले के समग्र विकास में सक्रिय सहभागिता निभाएं।

कलेक्टर डॉ सोनवणे ने ग्राम सायगोहन में नमन सेवा संस्था द्वारा प्राकृतिक खेती की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए अन्य लोगों से भी वहां जाकर कार्यों का अवलोकन करने का आग्रह किया।

उन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत नवांकुर संस्थाओं एवं प्रस्फुटन समितियों से कहा कि नदी पुनर्जीवन के महत्व को देखते हुए रिज टू वैली तकनीक के आधार पर कार्य करें।

स्व. खंडेलवाल स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में विश्वकर्मा टीम 106 के जवाब में आरपीएससी 49 रन पर सिमटी

सोहागपुर। स्व. मनोज खंडेलवाल की स्मृति में आयोजित विधायक ट्रॉफी 3 सोहागपुर प्रीमियर लीग बुधवार रात तीन नौवें दिन तीन क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता का पहला मैच विश्वकर्मा फर्नीचर एंड सीएनसी एवं आरपीएसजी टीमों के मध्य खेला गया। जिसमें विश्वकर्मा फर्नीचर एंड सी एन सी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 106 का स्कोर खड़ा कर दिया। इस टारगेट के जवाब में आर पी एस जी 49 रन बनाकर सिमट कर ऑल आउट हो गई। इस रोमांचक मुकाबले में मेन ऑफ द मैच साहेब चंदोंन को प्रदान किया गया। स्व. मनोज खंडेलवाल स्मृति विधायक ट्राफी 3 नाइट क्लब प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा मैच जीपीएस 11 एवं विश्वकर्मा फर्नीचर एंड सी एन सी के मध्य खेला गया। जिसमें विश्वकर्मा फर्नीचर एंड सी एन सी ने 143 रन बनाए। इसके जवाब में जी पी एस 11 केवल 87 रन बनाकर आउट हो गई। इस प्रतियोगिता में मेन ऑफ द मैच शुभम ग्राम मानेगांव को दिया गया। स्वर्गीय मनोज खंडेलवाल स्मृति विधायक ट्राफी 3 प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का तीसरा मैच आर पी एस जी और जी पी एस 11 के बीच हुआ। जिसमें जीपीएस 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 74 बनाए। वहीं बल्लेबाजी करते आर पी एस जी टीम ने 8 ओवर में सशक्त बल्लेबाजी करते लक्ष्य हासिल कर लिया । प्रतियोगिता में मेन ऑफ द मैच साहिल पटेल को प्रदान किया गया। इस नौवें दिन की प्रतियोगिता में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों के अलावा स्वर्गीय मनोज खंडेलवाल के सुपुत्र यश खंडेलवाल एवं आयोजक रामप्रसाद वार्ड पार्षद आशीष विश्वकर्मा मालवीय आदि उपस्थित थे।

हिडली में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 432 मरीजों का किया उपचार

बैतूल। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से जिले में 20 स्वास्थ्य शिविर लगाने की प्राप्त स्वीकृति के परिपालन में 7 मई को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिडली में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य रामचरण इरपाचे, सुनील टेकपुरे, विधायक प्रतिनिधि शिवदयाल आजाद, सरंपच रामा इवने, उप सरपंच राजू बसंतपुरे, जनपद सदस्य श्रीमती जयवंती इरपाचे एवं अन्य जनप्रतिधिरियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश परिहार ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ सचिन आहतकर के अनुसार शिविर में जिला चिकित्सालय की टीम जिसमें जिला चिकित्सालय से स्त्री रोग शिशु रोग दंत रोग, मानसिक रोग विशेषज्ञों द्वारा 55 गर्भवती माताएं, 8 शिशु रोग, दंत रोग 30, नाक-कान-गला 8, नेत्र रोग 30, मानसिक रोग 12, टीबी की स्क्रीनिंग 58, बीपी शुगर 102, सिकल सेल स्क्रीनिंग 27, अस्थि रोग 18 एवं अन्य 14 मरीजों कुल 432 मरीजों की जांच एवं उपचार किया गया। शिविर में बीपीएम, बीसीएम, सीएचओ, एएनएम, आशा कार्यकर्ता एवं महिला एवं बाल विकास विभाग उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुरमाडे ने बताया कि 9 मई को भीमपुर विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दामजीपुरा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा।

मैं भगवद्गीता हूँ

मैं भगवान श्रीकृष्ण की गीता हूँ...

नितिन वैद्य

मैं जन्मती नहीं मैं प्रकट होती हूँ। मोक्षदायिनी एकादशी का वही पावन दिवस है, जब कुरुक्षेत्र के रथ पर खड़े होकर योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने मुझे,अर्जुन को कहकर इस कलयुग के लिए अमृत बना दिया।

मैं बोल उठी, क्योंकि भगवान श्रीकृष्ण जानते थे,आने वाला कलयुग वेदों का गंभीर अध्ययन नहीं करेगा। मनुष्य जीवन की दौड़, लालसा, भ्रम और मोह में फँस जाएगा। 'इसलिए उन्होंने चारों वेदों का सार मुझे गीता के रूप में दे दिया।'

चार वेद जिनकी सार वाणी मैं हूँ
पहले चार वेदों को बताती हूँ-
ऋग्वेद - देवताओं की स्तुति (10,552 मंत्र)
यजुर्वेद - यज्ञ-विधि और कर्मकांड (1,975 मंत्र)
सामवेद - संगीत रूप में मंत्र (1,875 मंत्र)
अथर्ववेद - लोकजीवन और चिकित्सा (5,977 मंत्र)
कुल मंत्र - 20,379

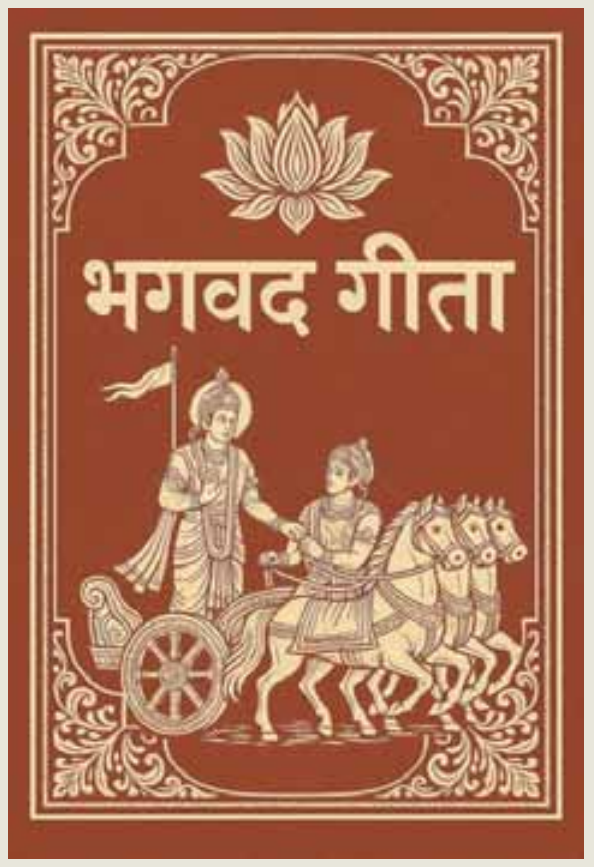

और इसी विशाल ज्ञान-सागर का सार,मैं भगवद्गीता अर्जुन को सुनाई गई। मैं महाभारत का केवल एक अंश हूँ, किंतु प्रभाव में सम्पूर्ण विश्व से सबसे बड़ी महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक और 18 पर्व हैं।

उनमें से मैं केवल भीष्म पर्व का एक छोटा भाग हूँ...परंतु प्रभाव में,मैंने असंख्य जीवन बदले, असंख्य आत्माओं को मोक्ष मार्ग दिखाया,और सम्पूर्ण विश्व का मार्गदर्शक ग्रंथ बन गई।

कुरुक्षेत्र का वह क्षण जब मैं जन्मी,उस पल जब अर्जुन ने निराश होकर अपना गांडीव रथ पर रख दिया,और कहा–

'हे केशव ! मैं युद्ध नहीं करूँगा।'

अर्जुन की वह हताशा,मानव का वह बड़ा प्रश्न–

'क्या सही है? क्या गलत?'

इसी ने मुझे जन्म दिया। आप विश्वास करें दुनिया के सारे ग्रंथ ऋषियों ने लिखे,परंतु मैं ही अकेली हूँ जो सीधे भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुई।

मेरे संवाद में चार पात्र हैं-
धृतराष्ट्र – 1 श्लोक
संजय – 41 श्लोक
अर्जुन – 84 श्लोक
भगवान श्रीकृष्ण – 574 श्लोक
कुल – 700 श्लोक
'अर्जुन ने 84 प्रश्न क्यों पूछे'

क्योंकि जीवों की 84 लाख योनियाँ होती हैं,और हर श्लोक एक-एक लाख योनि का प्रतिनिधि है। इसलिए मैं केवल एक संवाद नहीं,सम्पूर्ण सृष्टि की मार्गदर्शक हूँ।मेरे प्रथम और अंतिम शब्द भी मेरा सार कहते हैं

गीता में जहाँ से मैं प्रारम्भ होती हूँ,
पहला शब्द है– 'धर्म'
और जहाँ मैं समाप्त होती हूँ,
अंतिम शब्द है– 'मम'।
दोनों को जोड़ दो– 'धर्म + मम'
अर्थात् 'मेरा धर्म... मेरा कर्तव्य...'
यही तो मेरा सार है–
कर्तव्य का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। मैं जीवन-रहस्यों की मेनुअल हूँ
मैं मनुष्य को बताती हूँ,
कर्म क्या है?
अकर्म क्या है?
विकर्म क्या है?

कैसे बने स्थितप्रज्ञ,कैसे जिए समत्व बुद्धि,कैसे प्राप्त हो ममता से परे विशुद्ध भक्ति,मैं मार्ग दिखाती हूँ
ज्ञान से,
भक्ति से,
कर्म से...

और अंत में मनुष्य को उसके स्वधर्म तक ले जाती हूँ। मेरा स्थान पूजा घर में नहीं, मानव के हृदय में है। सच कहूँ तो,आपने मुझे पूजा घर में रखकर बस धूप-दीप दिखा दिया। पर मुझे वहाँ कैद मत कीजिए। मैं पढ़े जाने के लिए हूँ,समझे जाने के लिए हूँ,जीवन में उतारे जाने के लिए हूँ।

मैं विनती करती हूँ,अपने बच्चों को अपने पास बैठाइए,उन्हें मुझे प्रतिदिन पढ़ने को कहिए।चारों वेदों का सार उनके मन में स्वयं उतर जाएगा। विश्व मेरे मूल्य को समझ चुका है

'अब मेरे अपने भी समझें'

दुनिया में सबसे अधिक भाषाओं में मेरा अनुवाद हुआ है। मुझ पर 8000 से अधिक विद्वानों ने टीकाएँ लिखी हैं। विश्व के अधिकांश विश्वविद्यालयों में मुझ पर शोध हो रहा है। और आश्चर्य,भारत के न्यायालय में सत्य की शपथ वेदों पर नहीं,

मेरे 700 श्लोकों पर दिलाई जाती है।क्या यह नहीं बताता कि
मैं केवल एक ग्रंथ नहीं,मानव जीवन का ध्रुवतारा हूँ?
'मेरी सबसे बड़ी पीड़ा–और सबसे बड़ी प्रार्थना'

मैं आपकी हूँ...आपके घरों का अभिमान हूँ...पर सच में कैद भी मैं ही हूँ।

मुझे पूजा घर से मुक्त करें। मेरा संदेश युवाओं तक पहुँचाएँ। जीवन में उतारें। 'क्योंकि मैं वही दीपक हूँ जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है'।

श्री कृष्ण शरणं मम

संक्षिप्त समाचार

अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी ने विभिन्न क्षेत्रों का किया निरीक्षण

विदिशा (निप्र)। अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्री अनिल कुमार डामोर ने आज जनगणना कार्यों की प्रगति एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेने हेतु विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। इस दौरान बासौदा (ग्रामीण), शहरी क्षेत्र एवं त्योंदा क्षेत्र के चयनित वार्डों एवं गणना ब्लॉकों का निरीक्षण कर जनगणना कार्यों की समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान बासौदा ग्रामीण क्षेत्र में जनगणना कार्य पूर्ण करने वाले प्रगणकों एवं संबंधित कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी गईं तथा उनके कार्यों की सराहना की गई। साथ ही, शेष क्षेत्रों में कार्य की प्रगति का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसी क्रम में बासौदा (शहरी) एवं त्योंदा के विभिन्न वार्डों एवं गणना ब्लॉकों का निरीक्षण कर प्रगणकों को नामांकन एवं अन्य लंबित कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि जनगणना कार्य शासन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करना आवश्यक है।

आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त कर दबीर खान ने शुरू किया स्वयं का व्यवसाय

विदिशा (निप्र)। आईटीआई विदिशा में प्रशिक्षण प्राप्त कर युवाओं के सपने पूरे हो रहे हैं, ऐसी ही एक कहानी है विदिशा के ग्राम कागपुर के श्री दबीर खान की, जिन्होंने आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर अहमदाबाद की सुजुकी मोटर कंपनी में मोटर्स टेक्नीशियन के पद पर कार्य किया और आज वह अपने गांव कागपुर आकर बस गए हैं उन्होंने यहां वेल्डर वर्कशॉप फेब्रिकेशन का कार्य शुरू किया है उनकी वर्कशॉप के माध्यम से आज वह 20 हजार रुपये प्रतिमाह की आय प्राप्त कर रहे हैं। श्री दबीर खान पिता श्री रईस खान का जन्म ग्राम कागपुर तहसील नटेरन जिला विदिशा में एक मजदूर परिवार में हुआ उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हाईस्कूल शासकीय विद्यालय देव खजूरी से पूर्ण की एवं जिले के डिग्री कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की, तत्पश्चात् रोजगार की तलाश करते समय इन्हे इनके मित्रों ने आईटीआई के बारे में बताया। यह भी बताया कि कम समय एवं खर्च में कैसे वे कौशल प्राप्त कर रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त कर सकते है। इसके उपरान्त दबीर ने शासकीय आईटीआई विदिशा में सत्र 2019 में प्रवेश लिया और प्रशिक्षण पूर्ण कर 2020 में डिप्लोमा प्राप्त कर अहमदाबाद में सुजूकी मोटर्स में टेक्निशियन के पद पर ज्वाइन किया एक वर्ष वहाँ कार्य करने के बाद उन्होंने ग्राम कागपुर में वेल्डर वर्कशाप में फेब्रिकेशन का कार्य शुरू किया, जिससे उन्हे स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आज वह अपने गांव में रहकर ही प्रतिमाह 20 हजार रूपये तक औसत आय प्राप्त कर रहे हैं जिससे वे अपनी एवं अपने परिवार की आर्थिक जरूरते पूर्ण करने में खुद को सक्षम महसूस कर रहे हैं। इसके लिए उन्होने आईटीआई विदिशा एवं अपने प्रशिक्षकों का धन्यवाद प्रेषित किया है।

मां नर्मदा में प्रदूषण रोकने हेतु नर्मदा घाटों पर निषेधाज्ञा लागू

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदा नदी की स्वच्छता, धार्मिक महत्व एवं जन आस्था को ध्यान में रखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट नगर नर्मदापुरम श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश नर्मदा नदी के तट पर स्थित सेठानी घाट, कोरी घाट एवं पर्यटन घाट पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जारी आदेश के अनुसार इन घाटों पर पूजन एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक से निर्मित पूजन सामग्री, प्लास्टिक थैले, दीपक, कपड़े, पानी/तेल की बोतल एवं अन्य सामग्री को नर्मदा नदी में प्रवाहित करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रकार की सामग्री से घाटों पर कचरा एकत्रित होता है, जिससे लोक स्वास्थ्य, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा नदी प्रदूषित होती है। इसके साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सेठानी घाट, कोरी घाट एवं पर्यटन घाट पर पर्यटकों, स्थानीय निवासियों एवं श्रद्धालुओं द्वारा स्नान के दौरान साबुन, शैम्पू, सोडा, तेल एवं अन्य केमिकल युक्त डिटर्जेंट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करते हुए नर्मदा नदी की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें तथा पर्यावरण संरक्षण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर श्री बालागुरु के. की अध्यक्षता में टेक्सटाइल उद्योग पर जिला स्तरीय परामर्श बैठक आयोजित

सीहोर (निप्र)। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा जिला स्तर पर टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग प्रतिनिधियों के साथ परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक कलेक्टर श्री बालागुरु के. की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें उद्योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मध्यप्रदेश के वस्त्र निर्यात परिदृश्य एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया। कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने निर्देश दिए कि जिले में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सभी संबंधित विभाग और उद्योग आपसी समन्वय से कार्य करें और निर्यात बढ़ाने के लिए ठोस सुझाव देने के लिए कहा। उन्होंने बाजार पहुंच बढ़ाने एवं मुक्त व्यापार समझौतों (स्नञ्ज) के अधिकतम उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए कार्यशाला आयोजित कर विशेषज्ञों को बुलाया जाए। ताकि निर्यातकों को ऋण सुविधा एवं वित्तीय सहायता सरलता से उपलब्ध कराने की समुचित जानकारी दी जा सके। कलेक्टर ने निर्यात, लॉजिस्टिक्स, अधोसंरचना एवं पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर सुझाव देने को कहा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी उन्नयन, कौशल विकास एवं अनुपालन से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में उत्पाद विविधीकरण एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में जिला महाप्रबंधक श्री अनुराग वर्मा, एमपीआईडीसी के अधिकारी तथा जिले के उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित थे।

राहत मामलों में पीड़ितों को त्वरित उपलब्ध कराएं सहायता

सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए संपादित करें प्रक्रिया : कलेक्टर सोमेश मिश्रा

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने आयोजित समय-सीमा की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क एवं अन्य दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों में पीड़ितों को राहत राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। कलेक्टर श्री मिश्रा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए त्वरित कार्यवाही करें और पीड़ितों तक समय पर सहायता पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए संकट की घड़ी में प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान की जाए। बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करें। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा ने सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा करते हुए समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि नॉन-अटेंडेड शिकायतों की संख्या शून्य रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को अन अटेंडेड रखने पर विभिन्न अधिकारियों को जुर्माने जमा किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सोहागपुर यतेंद्र छारी, सीईओ माखननगर रंजीत ताराम, सीईओ केसला सुमन खातरकर, सीईओ पिपरिया प्रबल अरजरिया, एसएडीओ सोहागपुर एसके बर्दे, सीएमओ इटारसी ऋतु मेहरा को 500 रुपए प्रति शिकायत के अनुसार राशि को रेड क्रॉस सोसायटी (सहायता कोश) में जमा किए जाने के निर्देश दिए। जिससे भविष्य में जरूरतमंद नागरिकों को सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी शिकायतों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर जवाब दर्ज किया जाए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के संतुष्टिपूर्वक निराकरण पर प्रारंभिक सप्ताह से ही विशेष

ध्यान केंद्रित किया जाए, ताकि अनावश्यक लंबित प्रकरणों से बचा जा सके। साथ ही कलेक्टर ने प्रदेश स्तर पर होने वाली रैंकिंग एवं विभागीय ग्रेडिंग में निरंतर सुधार बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग अपनी ग्रेडिंग 'ए' से कम न होने दे और इसके लिए सतत प्रयास करते रहें। बैठक में कलेक्टर ने 1000 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कलेक्टर कार्यालय द्वारा चिन्हित सभी समय-सीमा प्रकरणों का सात दिवस के भीतर निराकरण किया जाए अथवा उनमें उचित कम्प्लायंस दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है, उनके संबंध में संबंधित प्रभारी अधिकारी को तत्काल सूचित किया जाए तथा उन्हें चरणबद्ध तरीके से बंद कराया जाए, ताकि लंबित प्रकरणों की सूची को अद्यतन रखा जा सके। बैठक में कलेक्टर ने सीएम एवं सीएस मॉनिट वाले प्रकरणों की भी समीक्षा करते हुए प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित कर अद्यतन सूची तैयार की जाए। समय-सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने जिले में संचालित गेहूं उपार्जन प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यकतानुसार केंद्रों पर संसाधन बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने स्पष्ट किया कि किसी भी उपार्जन केंद्र पर ट्रैक्टरों की लंबी कतार न लगे, इसके लिए समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने तौल कांटों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए, ताकि खरीदी प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

जिले के स्कूलों में समर कैंप शुरू -

खेल, कला और संगीत से बच्चों का हो रहा सर्वांगीण विकास

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में जिले के समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में 1 मई से 1 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस समर कैंप का मुख्य उद्देश्य बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा उनकी रचनात्मक क्षमताओं को निखारना है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। समर कैंप के दौरान विद्यार्थियों के लिए विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें खेल गतिविधियों के अंतर्गत खो-खो, बैडमिंटन, कबड्डी, चेस जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे बच्चों की शारीरिक क्षमता एवं टीम भावना का विकास हो रहा है। इसके साथ ही कला एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए पेंटिंग, स्केचिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसी गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। संगीत में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए विभिन्न वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण एवं संगीत सीखने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। समर कैंप का शुल्क मात्र 25 रुपए निर्धारित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसमें भाग लेकर लाभान्वित हो सकें। कैंप का समय प्रतिदिन सुबह 7रू00 बजे से 9रू00बजे तक रखा गया है। जिला प्रशासन ने ऐसे विद्यार्थियों से अपील की है, जिन्होंने अभी तक समर कैंप के लिए पंजीयन नहीं कराया है, वे शीघ्र अपने विद्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं और इस उपयोगी पहल का लाभ उठाएं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना: 200 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, एक मुस्लिम जोड़े का हुआ निकाह

गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकली बारात में जनप्रतिनिधियों ने नव दंपतियों को दिया आशीर्वाद

बैतूल (निप्र)। मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के तहत मुलताई जनपद के ग्राम चंदौरा में मंगलवार को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। भव्य आयोजन में 200 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ हिंदू जोड़ों के विवाह संपन्न हुए, वहीं एक मुस्लिम जोड़े का निकाह भी कराया गया। सामूहिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके, मुलताई विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य श्री सुधाकर पवार सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं। केंद्रीय

राज्य मंत्री श्री उइके ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे बेटियों के विवाह में आने वाली आर्थिक बाधाएं दूर हो रही हैं। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की चिन्ता कर पूरी भव्यता और गरिमा के साथ उनका विवाह संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विवाह एक ऐसा संस्कार है, जिसमें पुरुष और प्रकृति एक होकर एकाकार हो जाते है और नव वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से सभी नव युगल दंपतियों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। मुलताई विधायक श्री देशमुख ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना गरीब और

प्रशासन द्वारा की गई समुचित व्यवस्थाएं

कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए एसडीएम राजीव कहार के मार्गदर्शन में प्रशासनिक अमला व्यवस्थाओं में जुटा रहा। सम्मेलन स्थल पर बारातियों और घरातियों के लिए भोजन की विशेष व्यवस्था की गई। विशाल पंडाल, बैठने की सुविधा समेत अन्य जरूरी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई। नवविवाहित जोड़ों ने आयोजन की व्यवस्थाओं की सराहना की। आयोजन में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीणजन शामिल हुए।

जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ा सहारा बन रही है। इससे बेटियों के विवाह में आने वाला आर्थिक बोझ कम हो रहा है और उन्हें सम्मान के साथ नया जीवन शुरू करने का अवसर मिल रहा है।

कलेक्टर के निर्देश पर हुआ जनसुनवाई शिकायत पर एक्शन, बिजली समस्या का हुआ समाधान

क्षतिग्रस्त लाइन में किया गया सुधार किसानों को मिली राहत

नर्मदापुरम (निप्र)। जिले में जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुशासन की दिशा में जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार नागरिकों को उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में शिकायतकर्ता श्री अभय राजपूत एवं श्री अजय राजपूत द्वारा डोलरिया सबस्टेशन अंतर्गत ग्राम बमुरिया में कृषि लाइन को घरेलू फीडर से जोड़कर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति किए जाने से उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर द्वारा इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग (एमपीईबी) को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निर्देशों के परिपालन में विभागीय टीम द्वारा

मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें पाया गया कि 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र डोलरिया से जुड़े 11 के.व्ही. बाईखेडी कृषि फीडर के 12 पोल क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्राम बमुरिया के 4 वितरण ट्रांसफार्मरों से जुड़े 30 कृषि पंप उपभोक्ताओं को कृषि फीडर से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसके चलते वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इन उपभोक्ताओं को 11 के.व्ही. डुडूगांव घरेलू फीडर से बिजली प्रदाय की जा रही थी। समस्या के समाधान हेतु डोलरिया वितरण केंद्र द्वारा आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों का सुधार कार्य पूर्ण किया गया तथा कृषि फीडर को पुनः सुचारू किया गया। अब ग्राम में कृषि एवं घरेलू विद्युत आपूर्ति को पृथक-पृथक फीडरों से व्यवस्थित कर दिया गया है। सभी कृषि पंप कनेक्शन 11 के.व्ही. बाईखेडी फीडर से एवं घरेलू कनेक्शन 11 के.व्ही. डुडूगांव फीडर से संचालित किए जा रहे हैं। समस्या के समाधान के पश्चात शिकायतकर्ता श्री अभय राजपूत एवं श्री अजय राजपूत से संपर्क कर जानकारी ली गई, जिसमें उन्होंने समाधान को संतोषजनक बताते हुए जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

जिले में सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार हेतु आवेदन 15 मई तक

रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा) योजना के तहत मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए जिला स्तरीय और विकासखण्ड स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार तथा जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक समूह पुरस्कार योजना के तहत उन्नतशील कृषकों से 15 मई 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार में 25 हजार रू, विकासखण्ड स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार में 10 हजार रू की राशि प्रदान की जाती है।

जन जन की भागीदारी से वृहद रूप लेता ''नीर पखेरू अभियान''

नर्मदापुरम (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेशभर में जल संवर्धन एवं जल संरक्षण की दिशा में संचालित 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले में एक अभिनव पहल की गई है। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन में भीषण गर्मी के दौरान पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु 'नीर पखेरू अभियान' का संचालन किया जा रहा है। 'एक सकोरा पानी, पक्षियों की जिंदगानी' थीम पर आधारित यह अभियान जिले में वृहद स्तर पर संचालित हो रहा है और अब जन-जन का आंदोलन बनता जा रहा है। अभियान के माध्यम से पक्षियों के संरक्षण एवं उन्हें गर्मी के इस कठिन समय में भोजन एवं पानी उपलब्ध कराने की भावना घर-घर तक पहुंच रही है। अभियान में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों, विभिन्न कार्यालयों के साथ-साथ बच्चों एवं बुजुर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा उत्साहपूर्वक इस पहल में योगदान दिया जा रहा है। इसी क्रम में इटारसी में 'नीर पखेरू अभियान' से प्रेरित होकर 'अंबर सखा अभियान' का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत नगर के प्रसिद्ध स्वप्नेश्वरी हनुमान धाम मंदिर परिसर में पक्षियों के लिए सकोरे लगाए गए हैं।

गंभीर कुपोषित बालिका को मिला पूर्णतः स्वस्थ जीवन

कुपोषण से स्वस्थ जीवन की ओर

विदिशा (निप्र)। यह सफलता की कहानी विदिशा जिले की नटेरन परियोजना अंतर्गत आने वाले सेक्टर नटेरन 02 के एक आंगनवाड़ी केंद्र पमारिया 02 की है, जहाँ विभागीय प्रयासों एवं सामुदायिक सहयोग से एक गंभीर कुपोषित बालिका को पूर्णतः स्वस्थ जीवन प्रदान किया गया है। प्रारंभिक स्थिति की माने तो ग्राम के एक निर्धन परिवार में बालिका मुस्कान का जन्म 15 सितंबर 2024 को हुआ। जन्म के समय बच्ची का वजन मात्र 1.8 किलोग्राम एवं लंबाई लगभग 45 सेमी थी। जन्म से ही बालिका गंभीर कुपोषण (सेम श्रेणी) में थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माता स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर एवं पोषण

संबंधी जानकारी से अनभिज्ञ थी। परिवार में पोषण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अभाव था। इन परिस्थितियों के कारण बालिका को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा था और उसका वजन लगातार कम बना हुआ था। परियोजना नटेरन, जिला विदिशा के अंतर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमति रजनी अहिरवार द्वारा बालिका के घर निरंतर भ्रमण किया गया। उन्होंने माता-पिता को संतुलित आहार, स्तनपान एवं पूरक आहार के बारे में समझाया। नियमित टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच के लिए प्रेरित किया। आंगनवाड़ी केंद्र से मिलने वाली सेवाओं (पोषण आहार , वजन मापन आदि) से जोड़ा। प्रारंभ में परिवार ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, परंतु कार्यकर्ता ने धैर्यपूर्वक लगातार संपर्क बनाए रखा।

स्थिति गंभीर होने पर हस्तक्षेप: बालिका की स्थिति में अपेक्षित सुधार न होने पर , आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमति रजनी अहिरवार ने पर्यवेक्षक श्रीमती नीलम परिहार के संयुक्त प्रयास से बालिका मुस्कान को पोषण पुनर्वास केंद्र (एन आरसी) विदिशा में 17 नबंवर 2025 को भर्ती कराने का निर्णय लिया। पहली बार बालिका को छत्ब् में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकीय देखरेख में उपचार हुआ और बच्ची को संतुलित एवं ऊर्जायुक्त आहार दिया और माता को पोषण एवं देखभाल का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान बालिका के वजन में कुछ सुधार हुआ, परंतु वह अभी भी कुपोषण श्रेणी में बनी रही । एन आरसी में बच्ची मुस्कान को भर्ती कराते हुए कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक तथा साथ में बच्ची की माँ पुनः प्रयास और निरंतर निगरानी व जिले में संचालित पोषण संजीवनी अभियान अंतर्गत बालिका को सुपोषण किट वितरण करते हुए कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक तथा साथ में बच्ची की माँ कुछ समय बाद बालिका का वजन फिर अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पाया। इस पर पुनः संयुक्त प्रयासों से उसे दूसरी बार पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) विदिशा में 27 फरवरी 2026 में भर्ती कराया गया। दूसरी बार भर्ती के दौरान बालिका को विशेष पोषण आहार दिया गया। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। माता को व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) के माध्यम से जागरूक किया गया। इस बार परिणाम अधिक सकारात्मक रहे । एन आरसी में भर्ती के समय बच्ची का वजन 2.2 किलोग्राम एवं लम्बाई 46 सेमी थी, एन आरसी से डिस्चार्ज के समय बच्ची का वजन 3.0 किलोग्राम एवं लम्बाई 47 सेमी हो गई।

सुधार की प्रक्रिया: निरंतर प्रयासों, एन आरसी सेवाओं और आंगनबाड़ी केंद्र की नियमित मॉनिटरिंग के कारण बालिका गंभीर कुपोषण (सेम) से निकलकर मध्यम कुपोषण (मेम) श्रेणी में आई और धीरे-धीरे सामान्य श्रेणी में पहुंच गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आष्टा में आयोजित 200 बेटियों के सामूहिक विवाह सम्मेलन को किया वर्चुअली संबोधित

समाज के समृद्ध लोग सामूहिक विवाह सम्मेलनों में विवाह का करें ट्रेंड सेट : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सनातन संस्कृति में विवाह जन्म-जन्मांतर का पवित्र बंधन है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे वर-वधुओं के लिए आने वाला समय कई जिम्मेदारियां लेकर आता है। सभी परिवारों के लिए विवाह का आयोजन आनंद और उत्सव का वातावरण निर्मित करता है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक ही मंडप में समाज के विभिन्न वर्गों के बेटे-बेटी वैवाहिक बंधन में बंधते हैं, सामूहिक चेतना का यह उत्सव फिजूल खर्ची और दिखावे पर रोक का संदेश देता है। सरकार और समाज ने जब से सामूहिक विवाह का बीड़ा उठाया है तब से गरीब माता-पिता ने चैन की सांस ली है। समाज के समृद्ध लोग सादगी को

अपने व्यवहार में उतारे और सामूहिक विवाह सम्मेलनों में विवाह का ट्रेंड सेट करें। इससे समाज का हर वर्ग विवाह के अनावश्यक खर्च से बचेगा और उपलब्ध संसाधनों का परिवार के भविष्य निर्माण में उपयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि उन्होंने स्वयं भी अपने पुत्र का विवाह सामूहिक सम्मेलन में ही किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बेटियों की शिक्षा की चिंता करना और उसके लिए पर्याप्त प्रबंध करना, हर माता-पिता का दायित्व हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित 200 बेटियों के सामूहिक विवाह सम्मेलन को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित कर रहे है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर-वधु को आशीर्वाद प्रदान कर उनके परिजन को शुभकामनाएं दीं।

सामूहिक विवाहों के आयोजन से माता-पिता को नहीं लेना पड़ रहा है कर्ज

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दिसंबर 2023 से अप्रैल 2026 तक 1 लाख 70 हजार 187 बेटियों के विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत कराये गए है। योजना अंतर्गत अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन से आर्थिक रूप से कमजोर भाई-बहनों की बेटियां भी पूरे सम्मान के साथ विदा होती हैं। समाज का कोई भी वर्ग हो, बच्चों का विवाह हर माता-पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सामूहिक विवाहों के आयोजन से अब विवाह के लिए माता-पिता को कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है। समाज और सरकार एक-दूसरे के पूरक हैं। परिवर्तन के लिए समाज और सरकार दोनों का हाथ मिलाकर चलना जरूरी है। सामूहिक विवाह सम्मेलन जैसे आयोजन वर्तमान समय में समाज सेवा का सर्वोत्तम माध्यम बन चुके हैं। सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित कार्यक्रम में विधायक आष्टा श्री गोपाल सिंह इंजीनियर, अध्यक्ष जनपद पंचायत आष्टा श्रीमती दीक्षा सोनू गुणवान, जनप्रतिनिधि सहित वर-वधु और उनके परिजन उपस्थित थे।

भारत भवन में तीन दिनी 'प्रणाम उदंत मार्तंड' आज से

भोपाल। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के प्रसंग पर भारत भवन में आयोजित हो रहा है तीन दिवसीय बौद्धिक उत्सव 'प्रणाम उदंत मार्तण्ड'। 8 मई को प्रातः 10:30 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। विषय प्रवर्तन वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहूरकर करेंगे तथा अध्यक्षता आचार्य मिथिलेशनंदिनीशरण (अयोध्या) करेंगे। उद्घाटन सत्र का संचालन वरिष्ठ पत्रकार विनय उपाध्याय करेंगे।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिन के इस मीडिया कुंभ में देश के 9 राज्यों से विभिन्न भारतीय भाषाओं के 60 से अधिक पत्रकार, संपादक, लेखक, एंकर, विचारक, शिक्षाविद् और मीडिया विशेषज्ञ सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम में भारत भवन, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान, मप्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद भी सहयोगी हैं।

दो पुस्तकों और डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण- इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अनुभवों पर केंद्रित पुस्तक 'माखन के लाल' और 'कार्टून कथा' का लोकार्पण करेंगे। विश्वविद्यालय के प्रायोगिक अखबारों 'विकल्प', 'पहल' और 'अभ्युदय' के विशेषांकों का भी विमोचन होगा। इसी तरह इलेक्ट्रानिक मीडिया के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई तीन डाक्यूमेंट्री भी इस मौके पर रिलीज होगी।

रतलाम के डायल-112 हीरोज

सड़क हादसे में घायल हुए तीन लोगों को समय पर पहुँचाया अस्पताल

भोपाल। रतलाम जिले के थाना रिंगनोद क्षेत्र मेंडायल-112 जवानों की त्वरित प्रतिक्रिया और संवेदनशील कार्यवाहीसे सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल तीन व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुँचाकर उपचार दिलाया गया। समय पर मिली सहायता से घायलों को शीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकी।

07 मई को सुबह राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 भोपाल को सूचना प्राप्त हुई कि थाना रिंगनोद क्षेत्र अंतर्गतबिनोलीफंटा रोडपर दो मोटर साइकिलों की आमने-सामने से टक्कर हो गई है, जिसमें तीन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तत्काल पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना मिलते ही रिंगनोद थाना क्षेत्र में तैनात डायल-112 एफआरव्ही वाहन को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।

डायल 112 स्टॉफ आरक्षक चंद्रपाल सिंह एवं पायलट मंगलेश्वर सूर्यवंशीने मौके पर पहुँचकरपाया कि मोटरसाइकिल दुर्घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। डायल-112 जवानों ने बिना समय गंवाए सभी घायलों को एफआरव्ही वाहन की सहायता से तत्काल शासकीय अस्पताल जावरा पहुँचाया। डायल-112 जवानों की तत्परता से घायलों को समय पर उपचार मिल सका। डायल 112 हीरोज श्रृंखला के अंतर्गत यह घटना दर्शाती है कि मध्यप्रदेश पुलिस की डायल-112 सेवा हर आपात परिस्थिति में त्वरित सहायता, संवेदनशीलता और जनसेवा की भावना के साथ आमजन के लिए सदैव सक्रिय और प्रतिबद्ध है।

'महिमा स्वस्तिधाम-आस्था का अतिशय' की फिल्म का ट्रेलर 16 मई को होगा रिलीज

गणिनी आर्यिका 105 श्री स्वस्तिभूषण माताजी के सानिध्य में धार्मिक फिल्म का होगा विमोचन

इंदौर। रंगशाला प्रोडक्शन के बैनर तले बनी नई धार्मिक फिल्म 'महिमा स्वस्तिधाम की- आस्था का अतिशय' का विमोचन समारोह और ट्रेलर रिलीज 16 मई को केशोरायपाटन में होगा। केशोराय पाटन के दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में इस समय विराजित गणिनी आर्यिका 105 श्री स्वस्तिभूषण माताजी ससंघ के सानिध्य में इस धार्मिक फिल्म का विमोचन किया जाएगा। फिल्म के बारे में साधना जैन मादावत ने बताया कि भारतीय संस्कृति और जैन धर्म के गौरवशाली इतिहास को फिल्मी पर्दे पर उतारने की एक नई पहल की गई है। रंगशाला प्रोडक्शन के बैनर तले बनी नई धार्मिक फिल्म 'महिमा स्वस्तिधाम की- आस्था

का अतिशय' का पोस्टर विगत दिनों ही जारी किया गया था। अब फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर विमोचन किया जाएगा। साधना जैन मादावत ने बताया कि पोस्टर को राजस्थान के चंद्रवाचल तीर्थ, प्यावड़ी में गुरु मां स्वस्तिभूषण जी माताजी के 30वें दीक्षा दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। उन्होंने बताया कि यह फिल्म मुख्य रूप से 20वें तीर्थंकर श्री 1008 मुनिसुव्रतनाथ भगवान के स्वस्तिधाम (जहाजपुर) में प्रकट होने से जुड़ी अटूट श्रद्धा और चमत्कारी प्रसंगों को दिखाती है। इसके साथ ही, दर्शकों को पूज्य स्वस्तिभूषण माताजी के प्रेरणादायी जीवन के अनछुए पहलुओं को भी करीब से देखने का मौका मिलेगा।

फिल्म से जुड़ी खास बातें

जैन धर्म की आध्यात्मिक विरासत और तपस्या की शक्ति को जनता तक पहुंचाना फिल्म निर्माण का मुख्य उद्देश्य है। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से जहाजपुर सहित राजस्थान के ऐतिहासिक और धार्मिक शहरों में की गई है। साधना जैन मादावत ने बताया कि फिल्म का निर्देशन मुकेश दुबे ने किया है जबकि, सिनेमेटोग्राफी अनिकेत और संपादन इलैशा जैन ने किया है। कलाकार निकिता लविना, महावीर काला, हिमांशु, यथार्थ पाटनी, पारस जैन पार्श्वमणि, सुहानी मधु वेद, प्रकाश देशमुख और मनीष काला ने इसमें अपनी प्रभावी भूमिकाएं निभाई है। निर्देशक मुकेश दुबे ने बताया कि यह केवल एक फिल्म नहीं बल्कि भावनाओं को पर्दे पर उतारने की एक कोशिश है। वहीं फिल्म की संपादक इलैशा जैन ने इस प्रोजेक्ट को एक 'आध्यात्मिक यात्रा' बताया, जहां हर दृश्य में पवित्रता और संवेदनाओं का ध्यान रखा गया है। यह फिल्म न केवल धार्मिक दर्शकों को पसंद आएगी, बल्कि अपनी बेहतरीन प्रस्तुति और संगीत से हर किसी के दिल को छू लेगी।